हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 01 | अंक - 329 | बेमेतरा, बुधवार 16 जुलाई 2025 | रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित | कुल पेज - 8 | मूल्य - 5 रूपये

संक्षिप्त समाचार

आंध्र आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या में ट्रक पलटने से नौ मजदूरों की दर्दनाक मौत

अमरावती। आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में एक ट्रक पलटने से नौ मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। घायलों को राजमपेट के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दुर्घटना रात कडप्पा शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पुल्लमपेटा मंडल के रेड्डी चेरुवु कट्टा में हुई। पुलिस के अनुसार, हादसे के वक्त ट्रक में 21 दिहाड़ी मजदूर आम की बोरियों के ऊपर बैठे थे। करीब 30-40 टन आमों से लदा ट्रक रेलवे कोडुरु बाजार जा रहा था। राजमपेटा मंडल के एसुकापल्ली और आसपास के गांवों में बगीचों से आम तोड़कर लाए गए थे। झील के बांध पर आम से भरा ट्रक पलट गया और उसके ऊपर बैठे मजदूर नीचे दब गए। हादसे में बाल-बाल बचे ट्रक चालक ने पुलिस को बताया कि विपरीत दिशा से आ रही एक कार से टकराने से बचने की कोशिश में उसने नियंत्रण खो दिया और ट्रक झील के किनारे पलट गया। आठ मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।

बिहार में वज्रपात से नौ की मौत, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट

पटना। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात से नौ लोगों की मौत हो गई। मौसम में हुए अचानक बदलाव के कारण पटना, गया, वैशाली और बांका सहित कई जिलों में गरज के साथ बारिश हुई। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। मृतकों की उम्र 12 से 65 वर्ष के बीच है। वज्रपात से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बांका रहा, जहां चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कोहकारा की 12 वर्षीय करीना कुमारी, अमरपुर के अनिल यादव, फुलदीदुमार की सुलेक्षा देवी और बेलहर के पशुपालक विजय यादव शामिल हैं। गया जिले में सूर्यमंडल चेकपोस्ट के पास तीन बाइक सवार पर बिजली गिरी। इस हादसे में अंकित कुमार और विकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वकील मांझी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा, गया के मोहदा ब्लॉक में पशु चराने के दौरान रूपलाल यादव की बिजली गिरने से मौत हो गई।

उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे फिल्म निर्माता

नई दिल्ली। उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक पर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। फिल्म निर्माता ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फिल्म निर्माता के वकील ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एक-दो दिन में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का भरोसा दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया फिल्म निर्माता की ओर से कोर्ट में पेश हुए।

मां बोली-शब्दों में बयान नहीं कर सकती ये खुशी

शुभांशु 18 दिन आईएसएस पर रहने के बाद पृथ्वी सुरक्षित लौटे

नयी दिल्ली/ एजेंसी

शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर 18 दिन के प्रवास के बाद मंगलवार को खुशी और मुस्कुराहट के साथ पृथ्वी पर लौट आए. यह एक ऐसी उपलब्धि है, जो भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान की महत्वाकांक्षाओं को साकार करने का वादा करती है. लखनऊ में जन्मे शुक्ला और निजी 'एक्सिओम-4' मिशन के तीन अन्य अंतरिक्ष यात्री प्रशांत समयानुसार रात 2:31 बजे (भारतीय समयानुसार अपराह्न 3:01 बजे) कैलिफोर्निया के सैन डिएगो के निकट प्रशांत महासागर में उतरे. इस दौरान पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई. भारतीय वायु सेना में ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं. इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत रूस मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की थी. वह ऐसे पहले भारतीय भी बन गए हैं, जिन्होंने पृथ्वी की कक्षा में सबसे लंबे समय (20 दिन) तक रहकर अंतरिक्ष की यात्रा की. भारत, हंगरी और पोलैंड के लिए इस मिशन ने मानव अंतरिक्ष उड़ान की वापसी को साकार किया है, क्योंकि इन देशों के अंतरिक्ष यात्रियों ने 40 वर्षों से अधिक समय बाद पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की है. ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान 25 जून को फ्लोरिडा से उड़ा था और 28 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून को आईएसएस पहुंचा था. कक्षीय प्रयोगशाला में शुक्ला, कमांडर पैगी व्हिटसन तथा पोलैंड के मिशन विशेषज्ञ स्लावोज. उज्नान्स्की-विस्नीवस्की और हंगरी के टिबोर कापू सहित एक्सिओम-4 मिशन दल ने अगले 18 दिन 60 प्रयोगों और 20

संपर्क सत्रों में बिताए. ड्रैगन अंतरिक्ष यान ने 28 हजार किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा करते हुए एक्सिओम-4 चालक दल के सदस्यों को लेकर धीरे-धीरे गति कम करने और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए कई प्रक्रियाएँ पूरी कीं तथा प्रशांत महासागर में उतरने से पहले तीव्र गर्मी का सामना किया. कुछ ही मिनटों बाद ड्रैगन अंतरिक्ष यान को स्पेसएक्स के 'रिकवरी शिप शैनन' के ऊपर ले जाया गया, जहां शुक्ला और अन्य अंतरिक्ष यात्री मुस्कुराते हुए और कैमरों की ओर हाथ हिलाते हुए अंतरिक्ष यान से बाहर निकले. अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर तीन सप्ताह तक भारहीनता की स्थिति में रहने के बाद पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाने के लिए पैरों के सहारे चलवाने में शुक्ला और तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की 'ग्राउंड स्टाफ' ने मदद की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतरिक्ष प्रवास के बाद पृथ्वी पर लौटे शुभांशु शुक्ला को बधाई दी और कहा कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर 'एक्सिओम-4' मिशन के संचालन में उनकी भूमिका ने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है. उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, इस मिशन में शामिल सभी लोगों को मेरी बधाई.

यह गगनयान मिशन की दिशा में मील का पत्थर

पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला के सकुशल धरती पर लौट आने पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। इसमें पीएम मोदी ने लिखा 'मैं पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं, जो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से पृथ्वी पर लौट आए हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में, उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है।'

मानसून सत्र पर बोल कांग्रेस अध्यक्ष

सार्थक सत्र चाहता है विपक्ष दल-मल्लिकार्जुन खड़गे.....

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र से पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष एक सार्थक सत्र चाहता है। संसद का एक महीने तक चलने वाला मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होने वाला है। बैठक के बाद एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि विपक्ष 21 जुलाई से राज्यसभा का एक सार्थक सत्र चाहता है। इसके लिए कई रणनीतिक, राजनीतिक, विदेश नीति और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर बहस और चर्चा की आवश्यकता है, जो जनता के लिए बहुत चिंता का विषय हैं।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने धनखड़ के साथ अपनी बैठक की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि आज मैंने राज्यसभा के माननीय सभापति से मुलाकात की और एक उपयोगी बातचीत हुई। खरगे ने कहा, विपक्ष 21 जुलाई से राज्यसभा का सफल सत्र चाहता है।

केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीन के बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के महासचिव नूरलान येरमेकबायेव के साथ बैठक के दौरान।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

तलाक केस में सबूत बनेगी पति-पत्नी की गुप्त रिकॉर्डिंग

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 जुलाई 2025) को वैवाहिक विवादों पर महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। कोर्ट ने कहा, तलाक मामलों में पति-पत्नी के बीच हुई गुप्त बातचीत की मोबाइल रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य माना जाएगा। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा, आज पति पत्नी के रिश्ते आज इतने कमजोर हो चुके हैं कि वह एक-दूसरे पर निगरानी रखने लगे हैं, तो रिकॉर्डिंग विवाह संबंध की वास्तविक स्थिति दर्शाने वाली प्रासंगिक सामग्री बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

इस तरह के मामलों में निजता का अधिकार और साक्ष्य का अधिकार एक-दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन यदि रिकॉर्डिंग का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में सत्यता स्थापित करना हो तो उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

हत्या के मामले में दी जानी थी फांसी

यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की सजा टल गई.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

केरल की रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में होने वाली फांसी की सजा टल गई है। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो महदी की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी जानी थी। केरल के प्रभावशाली सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम ए पी अबूबकर मुसलियार और भारत सरकार के हस्तक्षेप से हो रही बातचीत के बाद यमन के स्थानीय अधिकारियों ने निमिषा की सजा स्थगित कर दी है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने हाल के दिनों में निमिषा प्रिया के परिवार

को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए लगातार प्रयास किए। भारतीय अधिकारी यमन के जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के साथ नियमित संपर्क में रहे हैं। बता दें कि निमिषा प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने साल 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तालाल अब्दो महदी की हत्या की थी। इस मामले में उन्हें 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी और उनकी अंतिम अपील 2023 में खारिज हो गई। 16 जुलाई 2025 को उन्हें फांसी देने की तारीख तय की गई थी। फिलहाल निमिषा यमन की राजधानी सना की जेल में बंद हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी निमिषा की फांसी को सजा रुकवाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल (एजीआई) ने कहा कि भारत सरकार प्रिया की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

मुझे जेल में खतरा है बिक्रम मजीठिया ने कोर्ट से की ये मांग

मोहाली। आय से अधिक संपत्ति के मामले में नाभा जेल में बंद अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें जेल में खतरा है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने अदालत में एक याचिका दाखिल की गई हैं। इस याचिका में उन्होंने अपील की है कि उन्हें नाभा जेल में खतरा है। उन्हें अलग से एक बैरक दी जाए जिसमें वह रह सके। याचिका को उनके वकीलों की तरफ से मोहाली अदालत में लगाया गया है। अब इस मामले में 14 जुलाई को सुनवाई होगी। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया अदालत के आदेश अनुसार 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में है। इसमें अदालत में सरकारी वकील को नोटिस भेज कर इस मामले में जवाब मांगा गया है।

सेना पर टिप्पणी का मामला

राहुल गांधी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर,5 मिनट में जमानत..

लखनऊ / एजेंसी

भारतीय सेना' पर टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार (15 जुलाई) को लखनऊ कोर्ट पेश हुए। राहुल के सरेंडर के बाद उनके वकील ने जमानत याचिका लगाई। कोर्ट ने मंजूर करते हुए राहुल को 5 मिनट बाद जमानत दे दी। कोर्ट ने 20-20 हजार के दो बॉन्ड पर राहुल को जमानत दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी के कोर्ट रूम में जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए। भारी सुरक्षा के बीच कांग्रेस सांसद लखनऊ के एमपी/एमएलए कोर्ट रूम के अंदर

पहुंचे। पुलिस ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा की कार को रोक दिया। उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशनके पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने 11 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दायर किया था। आरोप लगाया था कि 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय सेना पर विवादित टिप्पणी की थी। श्रीवास्तव ने दावा किया था कि राहुल ने 9 दिसंबर 2022 को भारत-चीन सीमा पर हुई झड़प का उल्लेख करते हुए कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं, जो उनकी दृष्टि में तथ्यों से परे और भ्रामक था। उनका कहना है कि ऐसे बयान से सैनिकों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ा और उनके परिवारों की भावनाएं भी आहत हुईं। भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा था कि चीन के सैनिकों ने भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया था।

मानसून सत्र का दूसरा दिन

जल जीवन मिशन पर भूपेश बघेल व साव के बीच नोक-झोंक

रायपुर। संवाददाता

विधानसभा के मानसून सत्र के आज दूसरे दिन जल जीवन मिशन के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बीच नोक-झोंक हुई। बघेल के सवालों का जवाब देते हुए साव ने कहा कि आप की सरकार के समय में नल कनेक्शन के 36 लाख आंकड़े दिखा दिए गए थे। वैरिफिक्केशन करवाने पर पता चला 21 लाख घरों में कनेक्शन ही नहीं हुए हैं। उप मुख्यमंत्री की तरफसे जो भी जवाब आया, विपक्षी विधायकगण संतुष्ट नहीं हुए और नारेबाजी करते हुए सदन से वाक आउट कर गए। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूछा कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में व्यय की गयी राशि की जानकारी दें? लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक कितने घरों के लोग जल की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं? उप मुख्यमंत्री अरूण साव की ओर से जवाब आया कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 31 लाख 16 हजार 398 घरों के लोग जल की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि जल जीवन मिशन में मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा एवं सूरजपुर जैसे जिलों में लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। अरुण साव ने कहा कि 2025 तक लगभग 31 लाख घरों में पानी दे चुके हैं। 2024 में यह योजना पूरी हो जानी चाहिए थी जो कि नहीं हुई। हमारी सरकार बनने के बाद 12 हजार 316 अतिरिक्त नलकूप कनेक्शन दिए गए। आप लोगों की जब सरकार थी तो यह योजना 2 साल विलंब से प्रारंभ हुई।

हमने 19 हजार 656 गांवों में नल कनेक्शन पहुंचाया। अभी की स्थिति में तेज गति से काम हो रहा है। बघेल ने कहा कि आपने हमारे समय का हवाला दे दिया। अब तो डबल इंजन वाली सरकार है। लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। फिर भी जल मिशन का काम कितने ही जिलों में पिछड़ा हुआ है। साव ने कहा कि सभी जिलों में काम चल रहा है। आपकी सरकार के समय में जल जीवन मिशन कनेक्शन के 36 लाख आंकड़े दिखा दिए गए। जब हमने वैरिफेकेशन करवाया तो पता चला 21 लाख घरों में ही कनेक्शन हुए हैं 15 लाख में नहीं। आप लोगों के समय में योजना पूरी हो गई होती तो आज ये हालात नहीं होते। बघेल ने कहा कि आप बता रहे हैं के हमने 36 लाख कनेक्शन दे दिए थे। पानी 21 लाख में ही पहुंच रहा है। दो साल में तो आप लोग 10 लाख कनेक्शन ही दे पाए, जबकि ट्रिपल इंजन वाली सरकार है। सवाल इस बात का है कि 21 लाख घरों में कैसे पानी नहीं पहुंच पा रहा है। बघेल की इस बात के समर्थन में उनके दल के विधायक उठ खड़े हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बघेल प्रश्न करने में सक्षम हैं। बाकी लोगों को हल्ला करने की जरूरत नहीं। प्रश्न को आगे बढ़ाया जाए। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि अब तो चार इंजन सरकार है। 20 माह के कार्यकाल में आपकी सरकार जल जीवन मिशन का 60 प्रतिशत काम कर पाई।

प्लांट में दुर्घटनाएं, बालेश्वर साहू ने विधानसभा में जताया आक्रोश

रायपुर। सक्ती जिले में स्थापित आर.के.एम. पॉवरजेन पॉवर प्लांट एवं डी.बी. पॉवर लिमिटेड में होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने आज विधानसभा में चिंता जताई। उन्होंने आक्रोशित होते हुए कहा कि प्लांट में अवैध डंपिंग के दौरान घायल हुए श्रमिक को मात्र 25 हजार मुआवजा देकर छुट्टी पा ली जाती है। प्रश्नकाल में बालेश्वर साहू का सवाल था कि जिला सक्ती के ग्राम उच्चपिंडा आर.के.एम. पॉवरजेन पॉवर प्लांट व ग्राम बड़ाहरदा डी.बी. पॉवर लिमिटेड उद्योगों के संबंध में विगत 3 वर्षों में कब, किसके द्वारा, किसको एवं क्या शिकायत की गई है? इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? जांच में कौन-कौन दोषी पाया गया तथा उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई इन उद्योगों में दुर्घटनाओं में कितनी मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए ? इस संबंध में कितना मुआवजा दिया गया व कितना शेष है।

गुरु के वचन और शिष्य की जिज्ञासा से बनता है संवाद का सेतु : रूपेंद्र साहू

गरियाबंद /मूक पत्रिका

आईएसबीएम विश्वविद्यालय में गुरु पूर्णिमा व्याख्यान श्रृंखला के अन्तर्गत मंगलवार को 'भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु-शिष्य संवाद' विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत में गुरु-शिष्य संबंधों की महत्ता और संवाद की परंपरा को उजागर करना था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सामाजिक सद्भाव विभाग प्रमुख रूपेंद्र साहू थे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक के सह जिला कार्यवाह भोपेन्द्र साहू उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ आनंद महलवार ने की। मुख्य वक्ता रूपेंद्र साहू ने कहा कि भारतीय परंपरा में संवाद केवल ज्ञान प्राप्ति का माध्यम नहीं रहा है, बल्कि यह आत्मबोध और समग्र विकास की प्रक्रिया का आधार रहा है। कबीर का उदाहरण देते हुए कहा कि कबीर गुरु के महत्वपूर्ण को न सिर्फ़ स्वीकार करते हैं बल्कि उसे श्रेष्ठता के साथ स्वीकार करते हैं। मनुष्य को पाँच रूपों में गुरु प्राप्त होते हैं। माता, पिता, शिक्षा देने वाले गुरु, दीक्षा देने वाले गुरु और परिस्थितियाँ। पहले गुरुकुल पद्धति थी और आश्रमों में दी जाने वाली शिक्षा केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें खेती, कारीगरी, युद्धकला, सेवा, अनुशासन और सह-अस्तित्व का प्रशिक्षण भी शामिल होता था। भोपेन्द्र साहू ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में 'गुरु' केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना हैं – जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर, जड़ता से चेतना की ओर ले जाते हैं। और 'संवाद' – वह सेतु है, जिसके माध्यम से यह ज्ञान, अनुभव और आत्मबोध शिष्य तक प्रवाहित होता है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ आनंद महलवार ने कहा गुरु कौन है? जो जीवन भर सीखता है वही श्रेष्ठ गुरु है। कई बार प्रकृति एवं परिस्थितियाँ हमारे लिए गुरु का कार्य करती हैं। गुरु का व्यक्तित्व ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। धन्यवाद ज्ञापन देते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ बीपी बोल ने कहा कि गुरु सर्वत्र, सर्वज्ञ और सर्व विद्यमान है। ज्ञान, अनुभव और संस्कार को गुरु की विस्तार देता है। कार्यक्रम का संचालन हिन्दी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ दिवाकर तिवारी ने किया।

बेमेतरा में सड़क सुरक्षा, नशा नियंत्रण और पशु क्रुरता पर समन्वय बैठक संपन्न

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टोरेट स्थित दिशा सभाकक्ष में बीते मंगलवार को सड़क सुरक्षा, पशु क्रूरता निवारण तथा नवीन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने की। बैठक में मई माह में हुई पिछली बैठक के निर्णयों की प्रगति की समीक्षा की गई और आगे की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहू ने नशीले पदार्थों की बढ़ती समस्या को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि नशा युवाओं का भविष्य अंधकारमय कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन मिलकर संगठित तरीके से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि जिले में अब तक नशे के कारोबार में संलिप्त कई व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है और मादक पदार्थों की जब्ती भी हुई है। उन्होंने विभिन्न विभागों से आपसी समन्वय के साथ नशा उन्मूलन के प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। बैठक में अपर कलेक्टर डॉ. अनिल बाजपेयी, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग सहित संबंधित समिति के सदस्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु आबकारी विभाग व नगरीय निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही, सड़कों के किनारे अनियमित रूप से लगे ठेले-गुमटियों को हटाकर व्यवस्थित करने एवं उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। सड़क सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों और बेरला क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है। इन क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड और अन्य सुरक्षा उपाय लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट के सामने सड़क सुरक्षा हेतु स्पीड लिमिट बोर्ड, डिवाइडर और अनिवार्य लाइट व्यवस्था के लिए एनएच विभाग से पत्राचार किया गया है। पशु क्रूरता के मुद्दे पर भी गंभीर चर्चा हुई, जिसमें यह बताया गया कि कुछ लोग अवैध रूप से पशुओं को एकत्र कर वध के उद्देश्य से अन्य क्षेत्रों में बेचते हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गश्त के दौरान ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी समय पर सूचना मिलने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैगा ग्राम अतरिया में क्षय एवं कुष्ठ उन्मूलन जनजागरण शिविर आयोजित

मुंगेली/मूक पत्रिका

कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले के लोरमी विकासखण्ड स्थित दूरस्थ पहुंचविहीन वनांचल बैगा ग्रामों में क्षय एवं कुष्ठ उन्मूलन जनजागरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के दौरान गांव के लोगों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक दवाई एवं परामर्श दिया जाता है। इसी कड़ी में बैगा ग्राम अतरिया में क्षय एवं कुष्ठ उन्मूलन जनजागरण शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक गिरीश कुर्रे के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में कुल 44 मरीजों की जांच की गई, जिसमें संदेहास्पद टीबी के 05, बुखार व सर्दी-खांसी व बुखार के 08, दाद, खाज, खुजली के 07, बीपी के 04, कमजोरी एवं हाथ-पैर दर्द के 11, कान दर्द 01, चर्मरोग के 03, दांत दर्द व एनएनसी 02, आंख संबंधी बीमारी के 03 मरीजों की जांच की गई और उन्हें दवाई एवं आवश्यक परामर्श दिया गया। जिला क्षय-कुष्ठ उन्मूलन अधिकारी डॉ. सुदेश रात्रे ने बताया कि शिविर में संदेहास्पद टीबी मरीजों की बलगम सीसीनॉट मशीन में जांच के लिए एकत्र किया गया। इसके साथ ही बचाव व नियंत्रण के लिए पाम्पलेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक अमिताभ तिवारी, पीएमडीटी समन्वय धीरज रात्रे, आरएचओ मणिलाल पैकरा, मितानिन सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही।

बच्चों के भविष्य की दिशा में सार्थक पहल- जिला पंचायत अध्यक्ष

कल्पना योगेश तिवारी ने ग्राम राखी और अकलवारा के स्कूलों का किया औचक निरीक्षण, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया भी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हुए बेमेतरा जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी ने मंगलवार को दो शासकीय विद्यालयों ङ्क ग्राम राखी (जोबा) की पूर्व माध्यमिक शाला एवं ग्राम अकलवारा की प्राथमिक शाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक तरफ जहां उन्होंने बच्चों से सीधा संवाद किया, वहीं, शैक्षणिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करते हुए शिक्षकों से कई विषयों पर संवाद कर सुधारात्मक सुझाव भी प्राप्त किए। जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी विद्यालयों के निरीक्षण दौरे के तहत सबसे पहले ग्राम राखी (जोबा) की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में पहुंची। वहां उन्होंने बच्चों से बातचीत की। उनकी कक्षाओं में जाकर ब्लैकबोर्ड पर पढ़ाया और उनकी पढ़ाई, लेखन क्षमता व समझ को भी परखा। उन्होंने बच्चों से शिक्षा, अनुशासन और उनकी आवश्यकताओं के बारे में खुलकर जानकारी ली। ग्राम राखी (जोबा) के बाद वह ग्राम अकलवारा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला पहुंचीं, जहां उन्होंने बच्चों के साथ संवाद किया। उन्होंने कक्षाओं में जाकर बच्चों की पढ़ाई का स्तर जाना, शिक्षकों की उपस्थिति, नियमितता और मिड-डे मील की स्थिति की गहन समीक्षा की। वहीं, बच्चों को स्कूल में मिलने वाली मिड-डे मील की गुणवत्ता की भी उन्होंने समीक्षा की। बच्चों को पौष्टिक आहार मिल रहा है या नहीं, इस पर विशेष ध्यान दिया। छात्र-छात्राओं की उपस्थिति की जानकारी लेकर उनके शिक्षा के प्रति रुझान को भी जाना। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिक्षकों से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए खुलकर चर्चा की और आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही बच्चों को आगे बढ़ने का साधन बनती है। इस औचक दौरे के बारे में पूछे जाने पर जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी ने कहा, ÷विद्यालयों का निरीक्षण कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य को गढ़ने की एक जिम्मेदारी है।÷ उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधि स्वयं जमीन पर उतरते हैं, तो व्यवस्था में विश्वास और पारदर्शिता दोनों बढ़ता है। निरीक्षण के पश्चात दोनों ही गावों के विद्यालय परिसरों में उन्होंने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, हरियाली और जीवनदायिनी प्रकृति की सौगात देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना योगेश तिवारी द्वारा किए गए इस निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि वह न केवल प्रशासनिक दायित्वों को गंभीरता से निभा रही हैं, बल्कि बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर संवेदनशीलता और सक्रियता दोनों प्रदर्शित कर रही हैं। यह पहल क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

आयुक्त कार्यालय में नवीन वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष का शुभारंभ

जगदलपुर/मूक पत्रिका

कमिश्नर बस्तर संभाग डोमन सिंह ने बीते मंगलवार को आयुक्त कार्यालय में नवीन वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवीन वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष के माध्यम से बस्तर संभाग के दूरस्थ क्षेत्र में अवस्थित एसडीएम, तहसील एवं जनपद पंचायत कार्यालय से सीधे जुड़कर विभागीय कार्यों सहित जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन स्थिति की समीक्षा करने में सहूलियत होगी। जिससे समय और श्रम दोनों की बचत के साथ ही मैदानी अधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकेगा। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर बीएस सिदार, आरती वासनिक एवं गीता रायस्त, अधीक्षण अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा पी मोहन सोनी सहित वरिष्ठ निज सहायक हरेंद्र जोशी और कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

दो मत्स्य पालकों को केसीसी योजना के तहत मिला 04 लाख से अधिक का चेक

- कलेक्टर ने सुनी आमजनों की समस्याएं, नियमानुसार निराकरण के दिए निर्देश

मुंगेली/मूक पत्रिका

जिला कलेक्टोरेट में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने जिले के आमजनों की मांगों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुनी और नियमानुसार निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर ने पथरिया विकासखण्ड के दो मत्स्य पालकों को केसीसी योजना के तहत मिला 04 लाख से अधिक का चेक प्रदान कर लाभान्वित किया। उन्होंने पथरिया विकासखण्ड के ग्राम अण्डा के दीपक कुमार कौशिक को मछलीपालन विभाग की केसीसी योजनांतर्गत 03 लाख रूपए का चेक और ग्राम चंदरगढ़ी के घनश्याम निषाद को 01 लाख 50 हजार रूपए का चेक प्रदान किया। दोनों हितग्राहियों दीपक और घनश्याम ने योजना का लाभ मिलने पर शासन-प्रशासन का आभार जताया। जनदर्शन में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस विभाग से संबंधित आवेदनों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान आमजनों द्वारा अपनी मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किए गए, इनमें आवास, शौचालय, पेयजल, राशन, पेंशन, विद्युत आदि मूलभूत सुविधाओं से संबंधित आवेदन थे। जनदर्शन में पथरिया विकासखण्ड के ग्राम भिलाई निवासी प्रदीप कोशले ने भूमिहीन योजना का लाभ दिलाने, संध्या कोशले ने महतारी वंदन योजना का लाभ दिलाने, ग्राम जगताकापा के ग्रामीणो ने नवीन ट्रांसफार्मर लगवाने, ग्राम गोइन्द्रा निवासी गेवन बाई ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने, ग्राम अमोरा के ग्रामीणों ने अघोषित विद्युत कटौती से निजात दिलाने, ग्राम बरछा की चम्पा ने पेंशन योजना का लाभ दिलाने, ग्राम भटगॉव की भूषण कुमार ने अपनी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटि सुधार कराने, मुंगेली विकासखण्ड के पीथमपुर की रामप्यारी ने शौचायल निर्माण की स्वीकृति दिलाने, ग्राम टिंगीपुर के श्री दशरथलाल ने सड़क दुर्घटना की मुआवजा राशि दिलाने, ग्रमा केशरूवाडीह सहित आसपास के ग्रामीणों ने तखतपुर से मौहाभाठा, कुकुसदा सड़क मार्ग की मरम्मत कराने, लोरमी विकासखण्ड के ग्राम खैरा के दिव्यांग लखनीचंद दिवाकर ने बैट्री चलित ट्रायसायकल दिलाने और ग्राम सांवतपुर के भरत सिंह मरकाम ने पीएम विश्वकर्मा योजनांतर्गत ऋण दिलाने सहित अन्य आवेदकों ने अपनी मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के संबंध में आवेदन सौंपा।

विश्व जनसंख्या पखवाड़ा 2025: जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर रणबीर शर्मा के निर्देशानुसार विश्व जनसंख्या पखवाड़ा के अवसर पर मंगलवार 15 जुलाई को परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारी डॉ अमृत लाल रोहडेलकर, नोडल अधिकारी डॉ बी एल राज द्वारा विश्व जनसंख्या पखवाड़ा 2025 जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण लगातार संसाधनों की कमी हो रही है साथ ही जनसंख्या बढ़ने से कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। जिनमें प्रमुख रूप से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याओं का सामना लगभग हर देश को करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनसमुदाय को जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं से जागरुक करने तथा उनसे निपटने हेतु जनसंख्या नियंत्रण के विभिन्न अस्थाई और स्थाई साधनों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रति वर्ष 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस से जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। 11 जुलाई से 18 जुलाई तक आयोजित पखवाड़े के दौरान जिले के स्वास्थ संस्थाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसमें सास बहु सम्मेलन, पुरुष नसबंदी कैम्प लगाना, गर्भ निरोधक अस्थाई और स्थाई साधनों मुख्यतः आईयूसीडी निवेशन, गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा, छाया एवं माला एन. गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन, तथा पुरूष एवं महिला नसबंदी के बारे में प्रचार प्रसार करना और लक्षित दंपत्ति को उपयोग के लिए प्रेरित कर अपनाने हेतु परामर्श देने के साथ छोटे परिवार की महत्ता को विशेष रूप से बढ़ावा देना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले को मितानिनों के साथ सभी लक्षित दंपति परिवार में गृह भेट कर उचित परामर्श देने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं। जनसंख्या स्थिरिकरण पखवाड़ा 11 जुलाई से 18 जुलाई 2025 तक मनाया जा रहा है इस सम्बन्ध में जनजागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु सारथी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया उक्त अवसर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बेमेतरा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी परिवार कल्याण, डीपीएम, आर एम एन सी एच जिला समन्वयक एवं समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे ।

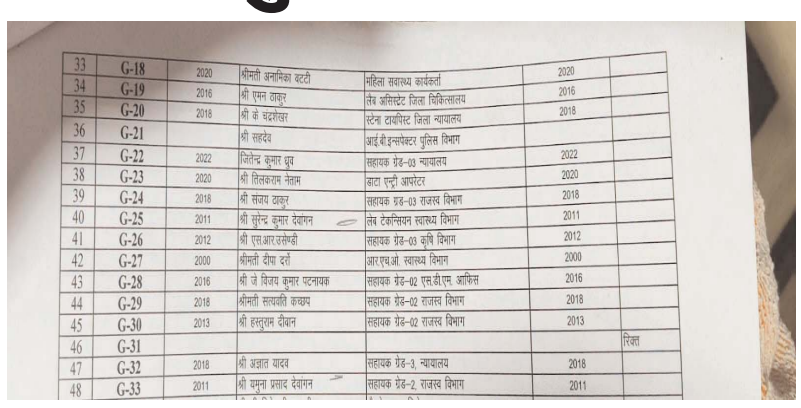

संविदा लैब टेक्रिशियन को किस नियम के तहत आबंटन किया गया क्वार्टर - स्वास्थ्य विभाग में भर्राशाही चरम पर

बर्खास्त लैब टेक्निशियन 5 वर्षो से जमा हुआ है सरकारी क्वार्टर में

- स्वास्थ्य विभाग रसूखदार लैब टेक्रिशियन के आगे है नतमस्तक
- सैकड़ों कर्मचारियों ने मकान के लिए लगाया है आवेदन, नही मिल पा रहा क्वार्टर

43	G-28	2016	श्री जे विजय कुमार पटनायक	सहायक ग्रेड-02 एस.डी.एम. आफिस	2016	
44	G-29	2018	श्रीमती सत्यवति कच्छप	सहायक ग्रेड-02 राजस्व विभाग	2018	
45	G-30	2013	श्री हस्तुराम दीवान	सहायक ग्रेड-02 राजस्व विभाग	2013	
46	G-31					रिक्त
47	G-32	2018	श्री अज्ञात यादव	सहायक ग्रेड-3, न्यायालय	2018	
48	G-33	2011	श्री यमुना प्रसाद देवांगन	सहायक ग्रेड-2, राजस्व विभाग	2011	

दंतेवाड़ा/मूक पत्रिका

स्वास्थ्य विभाग में शासकीय आवास आबंटन मामले में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग का एक बर्खास्त संविदा कर्मचारी वर्षो से शासकीय आवास में कब्जा जमाए हुए हैं। सैकड़ो ऐसे कर्मचारी हैं जो मकान के लिए वर्षो से आवेदन लगाए इंतजार कर रहे हैं मगर उन्हें आवास खाली नहीं होने की बात कहकर आवास आबंटन नहीं किया जा रहा है वहीं दुसरी ओर अपात्र लोगों को उनकी रसूख देखकर विभाग नियम विरूद्ध आवास दे रखा है जिसमें वे दशकों से जमे पड़े हैं। शासकीय क्वार्टर में पात्रता नहीं होने के बाद भी सालों से कब्जा जमाए होने का एक मामला स्वास्थ्य विभाग से निकलकर सामने आया है। मामला यह है कि दंतेवाड़ा जीएडी कालोनी के मकान नंबर जी 25 में सुरेंद्र देवांगन नाम का एक शख्श वर्ष 2011 से निवासरत है। सुरेंद्र देवांगन पहले जिला अस्पताल में लैब टेक्रिशियन था। उस पर शेर खाल की तस्करी का आरोप लगा था जिसके बाद उसे जेल भी जाना पड़ा था। मामला अभी सब जूडिशियल है। उक्त प्रकरण के बाद लैब टेक्रिशियन संविदा कर्मचारी सुरेंद्र कुमार देवांगन को स्वास्थ्य विभाग ने 23 मार्च 2021 को बर्खास्त कर दिया था। यहां तक तो सब सही है। अब बड़ा सवाल स्वास्थ्य अधिकारियों पर यह उठता है कि बर्खास्तगी के 4 साल बाद भी देवांगन से आज पर्यंत तक शासकीय आवास खाली नहीं कराया गया है। बर्खास्त संविदा लैब टेक्रिशियन श्री देवांगन आज भी जीएडी कालोनी के जी 25 क्वार्टर में शान से पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। वर्तमान में संजीवनी पैथोलॉजी लैब के संचालक भी हैं। बता दें कि शासकीय आवास नियमतः संविदा कर्मचारियों को एलॉट करने का नहीं होता है। रेगुलर कर्मचारी ही इसके पात्रता रखते हैं तो फिर किस नियम के तहत संविदा कर्मचारी को विभाग ने शासकीय मकान एलॉट किया यह भी जांच का विषय है। दुसरी बात यह कि स्वास्थ्य अधिकारी को आज की तारीख में यह मालुम है कि फ्लां व्यक्ति जो उनके विभाग से बर्खास्त किया गया है वो आज भी शासकीय आवास में बना हुआ है तो फिर इस मामले में अब तक मकान खाली करवाने की कारवाई क्यों नहीं की गई? बता दें कि बर्खास्त लैब टेक्रिशियन सुरेंद्र देवांगन काफी रसूखदार है। इस वजह से विभाग का वर्दहस्त उसे प्राप्त है जिसके चलते उसे शासकीय मकान में रहने का सौभाग्य मिला हुआ है। यहां यह भी बताना आवश्यक है कि सैकड़ों ऐसे शासकीय कर्मचारी और अधिकारी हैं जो दीगर जिले से यहां सेवा देने आए हैं उन्हें आवेदन के बाद भी शासकीय क्वार्टर एलॉट नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्वार्टर खाली ही नहीं है। 5 से 10 हजार रूपए महिने के दर से किराए के मकान लेकर कई कर्मचारी रहने को मजबूर हैं वहीं दूसरी ओर विभाग ऐसे अप राधी तत्वों पर मेहरबानी दिखा रहा है जो समझ से परे है। नियम विरूद्ध संविदा कर्मचारी को मकान एलॉट करने वाले स्वास्थ्य विभाग के तात्कालीन अधिकारी और आवास देखने वाले तब के कर्मचारी पर भी नियमतः कारवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को तत्काल ऐसे बर्खास्त कर्मचारियों से शासकीय आवास खाली कराकर किसी जरूरतमंद कर्मचारी को आवास उपलब्ध करवाए यही नियमतः सही होगा। वर्जन - शासकीय आवास में बर्खास्त लैब टेक्रिनशियन द्वारा कब्जा जमाए होने की शिकायत मिली है। हमने उन्हें नोटिस जारी किया है। अगर क्वार्टर तय समय पर खाली नहीं किया जाता है तो हम अग्रिम कानुनी कारवाई के लिए बाध्य होंगे। जितने वर्षो से उसमें निवास किया जा रहा है तब से लेकर अब तक गणना कर पूरी राशि वसूल कर शासकीय खजाने में जमा करवाया जाएगा। (अजय रामटेके) सीएमएचओ स्वास्थ्य विभाग दंतेवाड़ा।

कलेक्टर ने दो अनुग्रह प्रतिकर मामलों में कुल 17 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की

दंतेवाड़ा/मूक पत्रिका

जिला प्रशासन दंतेवाड़ा द्वारा बीते मंगलवार को दो महत्वपूर्ण अनुग्रह प्रतिकर मामलों में कुल 17 लाख रुपये की सहायता राशि संबंधित पात्र हितग्राहियों को प्रदान की गई। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने इन प्रकरणों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत रूप से सहायता राशि वितरित की और पीड़ित परिवारों को शासन की ओर से संवेदना व्यक्त की। यह सहायता छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियमों के अंतर्गत, राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 361 दिनांक 18 दिसंबर 2009 तथा क्रमांक 675 दिनांक 21 अक्टूबर 2019 के दिशा-निर्देशों के तहत स्वीकृत की गई है।

पहला प्रकरण: बस्तर फाइटर आरक्षक विजय कुमार कश्यप घायल-प्रथम मामला त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान माओवादी गतिविधियों के विरोध में चलाए जा रहे सुरक्षा गश्त-सर्चिंग अभियान से संबंधित है। दिनांक 4 फरवरी 2025 को ग्राम पुरंगेल नाला के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए स्पाइक रॉड (नुकीली कीलयुक्त अवरोधक) से बस्तर फाइटर बल के आरक्षक क्रमांक 1348 विजय कुमार कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से रायपुर स्थित श्री नारायणा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका उपचार कराया गया। यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया गया, जिसके पश्चात आयोग द्वारा ?2.00 लाख की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की गई।

दूसरा प्रकरण: प्रधान अध्यापक श्री करण सिंह नेताम का निधन-द्वितीय मामला जनपद पंचायत गीदम अंतर्गत पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 से जुड़ा हुआ है।दिनांक 13 फरवरी 2025 को तृतीय प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने के उपरांत कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गीदम में पदस्थ प्रधान अध्यापक करण सिंह नेताम अपने निवास की ओर लौट रहे थे। इस दौरान शिशु मंदिर स्कूल, गीदम के समीप एक गंभीर सड़क दुर्घटना में वे घायल हो गए। उपचार हेतु उन्हें तत्काल रायपुर स्थित रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती किया गया, परंतु 27 फरवरी 2025 को उनका निधन हो गया।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस अत्यंत दुखद घटना को संज्ञान में लेते हुए उनके वैध उत्तराधिकारी, श्रीमती सुमित्रा नेताम, निवासी ग्राम करप, सड़कपारा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को 15 लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की गई।

संवेदना और प्रशासनिक उपस्थिति-दोनों प्रकरणों में बीते मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत द्वारा औपचारिक रूप से सहायता राशि संबंधित परिवारों को सौंपी गई। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी मूलचंद चोपड़ा उपस्थित रहे।

नदी -नालों में बाढ़ की स्थिति में फिल्ड पर रहे एक्टिव - कलेक्टर

तय समय -सीमा में गिरादावरी कार्य पूरा करने के निर्देश

- कलेक्टर ने की विभागीय कार्यो की समीक्षा

बलौदाबाजार/मूक पत्रिका

कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को समय -सीमा की बैठक में विभागीय कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने बरसात में जिले के नदी -नालों एवं जलाशयों में जल भराव की स्थिति को देखते हुए राजस्व अमले को फिल्ड पर एक्टिव रहने के निर्देश दिये। कलेक्टर सोनी ने कहा कि जले में अति वृष्टि के कारण नदी -नालों में जल भराव से कोई जन हानि या पशु हानि जैसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। एसडीएम व तहसीलदार सतत मॉनिटरिंग करें और मैदानी अमलों को अलर्ट रखें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को आगामी अक्टूबर माह तक पूर्ण कराने मिशन मोड़ में कार्य करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये।उन्होंने सीमांकन, आरबीसी 6-4 एवं भू अर्जन के प्रकारणो के निराकरण में भी तेजी लाने कहा।

कलेक्टर ने राज्य शासन के निर्देशानुसार खरीफसीजन 2025 में फसल गिरदावरी 1 अगस्त से 30 सितम्बर 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने गिरदावरी कार्य हेतु पटवारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने खराब एवं जर्जर सड़कों के मरम्मत की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जर्जर सड़कों के मरम्मत में तेजी लाने के निर्देश दिये। इस दौरान स्वामित्व योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, आधार सिडिंग,आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, धरती आबा अभियान, समय -सीमा के तहत दर्ज आवेदनों के निराकरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुश्री दीप्ति गोते, मिथलेश डोंडे सहित, एसडीएम, जनपद सीईओ एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

डेढ़ साल के भीतर भाजपा की साय सरकार ने चौथी बार बढ़ाएं बिजली के दाम, जनता की जेब में सरकार कर रही डकैती

भाजपा की वर्तमान साय सरकार के डेढ़ साल में कुल वृद्धि 80 पैसे अर्थात 13 प्रतिशत बढ़ोत्तरी

दंतेवाड़ा/मूक पत्रिका

जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिले, व प्रदेश मैं अघोषित बिजली कटौती, लगातार बढ़ती बिजली समस्या को लेकर कांग्रेस प्राधिकारी द्वारा पत्रकार वार्ता किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर लूटने का काम भाजपा सरकार ने किया है। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, गैर घरेलू बिजली की दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है।सर्वाधिक बढ़ोतरी कृषि पंप के बिजली के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करके की गई है। छत्तीसगढ़ के किसान इस सरकार की दुर्भावना और उपेक्षा के चलते पहले ही खाद, बीज और बिजली कटौती से परेशान हैं, अब कृषि पंप में बिजली की दर बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ रही है भाजपा सरकार इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जनता को लूटने के तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। 2003 से 2018 तक भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने हर साल बिजली के दामों में वृद्धि की। 2003 में छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 रुपए 30 पैसे के दर पर बिजली मिला करती थी, जिसे 15 साल के कुशासन के बाद रमनसिंह के समय ही 6 रुपए 40 पैसे तक बढ़ाया गया, जिसे चुनाव चुनावी वर्ष 2018 में मात्र 20 पैसे घटकर 6 रुपया 20 पैसे किया गया।पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में पूरे 5 साल का नेट वृद्धि यदि देखें तो मात्र दो पैसे का था. जो ऐतिहासिक तौर पर सबसे न्यूनतम था।

भक्तों ने लिखे मन्नत पत्र मां गर्लफ्रेंड से शादी करवा दीजिए, एनएमडीसी में नौकरी लगवा दीजिए

05 माह बाद खुली मां दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटी

दंतेवाड़ा/मूक पत्रिका

लंबे अरसे करीबन 5 माह बाद बीते सोमवार को फिर से दंतेश्वरी माता मंदिर की दान पेटी खोली गई इसमें नगदी सोने चांदी के साथ-साथ मन्नत वाले भक्तों के पत्र भी मिले जिसमें किसी ने गर्लफ्रेंड से शादी की मन्नत मांगी थी तो किसी ने एनएमडीसी में नौकरी किसी ने परिवार में सुख शांति मां दंतेश्वरी मंदिर में रोज सैकड़ो की तादाद में भगत आते हैं जो दान पेटी में दान करने के अलावा सोना चांदी का भी दान करते हैं देश के अलावा विशेष मौके नवरात्रि में विदेश से भी यहां ज्योति कलश जलवे जाते हैं भक्तों ने 11 लाख 18194 दान किया है फरवरी में दान में 19 लाख 23723 मिले थे मैं जी की दान पेटी सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर परिसर में खोली गई जिसमें टेंपल कमिटी के मेंबर और मंदिर के प्रमुख लोगों के द्वारा दान की राशि की गिनती की गई।

नवरात्रि पर्व पर आता है एक करोड़ से अधिक का चढ़ावा-दंतेश्वरी मंदिर की ख्याति तीन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है दंतेश्वरी माता की टेंपल कमिटी की करोड़ों की संपत्ति है यहां सर्दी नवरात्रि एवं चैत्र नवरात्रि में सबसे अधिक चढ़ावा चढ़ाया जाता है एक करोड़ से अधिक का चढ़ावा इस समय मंदिर में ज्योति क्लास और दान पेटी में भक्तों द्वारा चढ़ाया जाता है दंतेश्वरी मंदिर अब भाव बन गया है जिसकी वजह से भक्तों की संख्या भी बढ़ गई है दान के पैसे से मंदिर के सारे खर्चों की पूर्ति भी की जाती है फागुन मेले के लिए अलग से बजट का प्रावधान होता है दंतेश्वरी माता के मंदिर में जो भी चांदी का चढ़ावा मिलता है इससे सिक्के बनवाए जाने लगे हैं जो नवरात्रि पर्व में लोगों को विशेष राशि प्रदाय करने पर चांदी के सिक्के दिए जाते है ।

नक्सलियों का कबूलनामा: एक वर्ष में 357 नक्सली मारे गए, केंद्रीय कमेटी ने जारी किया प्रेस नोट

बस्तर/मूक पत्रिका

नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने एक प्रेस नोट जारी कर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए अपने सदस्यों की पुष्टि की है। जारी दस्तावेज़ के अनुसार, पिछले एक वर्ष के दौरान कुल 357 नक्सली मारे गए, जिनमें 136 महिलाएं भी शामिल हैं। प्रेस नोट के अनुसार, मारे गए नक्सलियों में 4 केंद्रीय कमेटी (सीसी) सदस्य और 15 राज्य कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं, जो संगठन के लिए एक बड़ी क्षति माने जा रही है। सबसे अधिक नुकसान दण्डकारण्य क्षेत्र में हुआ है, जहाँ 281 नक्सली मारे गए। नक्सलियों ने इस सूचना के साथ 24 पेज की एक बुकलेट भी जारी की है, जिसे गोंडी भाषा और अंग्रेज़ी में प्रकाशित किया गया है। इसमें मारे गए नक्सलियों को 'शहीद' बताते हुए, उनकी स्मृति में 28 जुलाई से 3 अगस्त तक 'शहीदी सप्ताह' मनाने की घोषणा की गई है। सुरक्षा विशेषज्ञ इस बयान को नक्सल संगठन की वर्तमान स्थिति में कमजोरी की खुली स्वीकारोक्ति मान रहे हैं।

नक्सलियों ने दो शिक्षादूतों को बेरहमी से उतारा मौत के घाट, इलाके में दहशत का माहौल

बीजापुर/मूक पत्रिका

जिले के नेशनल पार्क अंतर्गत फरसेगढ़ थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां नक्सलियों ने दो शिक्षादूतों की निर्मम हत्या कर दी।नक्सलवाद की आग एक बार फिर शिक्षा के मंदिरों तक पहुंच गई है।यह दर्दनाक वारदात पिल्लूर और टेकामेटा गांवों में बीती रात घटित हुई, जिसमें मुखबिरी के संदेह में शिक्षकों विनोद मड़े और सुरेश मेट्टा को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया गया।मिली जानकारी के अनुसार, दोनों शिक्षादूतों की हत्या के पीछे नक्सलियों द्वारा मुखबिरी के संदेह को वजह बताया जा रहा है। हालाँकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीणों में चर्चा है कि नक्सलियों ने उन्हें पहले धमकी दी थी।विनोद मड़े, बीजापुर ब्लॉक के कोंडापल्ली गांव के प्राथमिक स्कूल में शिक्षादूत के पद पर कार्यरत थे। वहीं सुरेश मेट्टा, टेकमेट्टा गांव के स्कूल में बच्चों को शिक्षित कर रहे थे।यह घटना फरसेगढ़ थाना क्षेत्र नेशनल पार्क में घटित हुई है, जो पहले से ही घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियों के कारण सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण इलाका माना जाता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें घटनास्थल की ओर रवाना हो गई हैं, मगर सड़क मार्ग और सुरक्षा खतरों के कारण बलों को वहां तक पहुंचने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है।इस घटना के बाद गांवों में दहशत का माहौल है। कई शिक्षकों ने दूरस्थ इलाकों में ड्यूटी करने को लेकर चिंता जताई है। अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। शवों की स्थिति और स्थान की भी पुष्टि नहीं हो पाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सुरक्षा बलों के पहुंचने के बाद घटना की पूरी जानकारी सामने आएगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग में खुलकर हो रही मनमानी : तुलिका कर्मा

- तबादले के बाद भी बाबू को रिलीव नहीं कर रहे अधिकारी, अधिकारी और बाबू मिलकर लूट रहे हैं विभाग को

दंतेवाड़ा/मूक पत्रिका

महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक ग्रेड 2 संतोष झा के तबादले का मामला अब पूरी तरह से गरमा गया है। तबादले पर हो रही लेटलतीफी को लेकर जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि किसी भी शासकीय कर्मचारी का तबादला होने पर नियमतः उसे नवीन पदस्थाना स्थान पर जाकर ज्वाईंग देना होता है। महिला बाल विकास विभाग ने लिपिक तबादले के बाद भी उसे भारमुक्त नहीं करना और नियम-कायदों का हवाला देकर उसे पखवाड़े भर से रोके रखना इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं बाबू और अधिकारी का गठजोड़ है। महिला एवं बाल विकास विभाग में तमाम प्रकार की योजनाएं संचालित होती है। विभाग में कई सारे योजनाओं में अनियमितताएं है। तुलिका ने कहा कि महिला बाल विकास विभाग में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसमें बाबू और जिला कार्यक्रम अधिकारी दोनों की मिलीभगत कई बार सामने आ चुकी है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि बाबू के चले जाने से जिला कार्यक्रम अधिकारी के कई काले कारनामे सामने आ सकते हैं, जिससे वह डरे हुए हैं और बाबू को रिलीव नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी विभाग संतोष झा का ताबदला भैरमगढ़ हुआ था पर साहब की मेहरबानी के चलते उनका तबादला रोक दिया गया था। तुलिका ने महिला बाल विभाग के अधिकारी वरूण नागेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाबू से उनकी मिली भगत जग जाहिर है। संतोष झा के ताबदले के बाद उनकी जगह बचेली से नवीन पदस्थापना हो चुकी है पर आज दिनांक तक बाबू को भारमुक्त नहीं किया गया है। बताया जाता है कि महिला बाल विकास विभाग की ओर से होने वाले मुख्यमंत्री कन्या विवाह में बाबू और साहब ने मिलकर लाखों के वारे न्यारे किए हैं। करीब डेढ़ दशक से एक स्थान पर जमे रहने के कारण बाबू ने अपार संपत्ति अर्जित कर ली है। तुलिका ने कहा कि इस मामले में भाजपा के नेताओं ने भी आंखें मूंद रखी है। कई बार शिकायत होने के बाद भी जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं लिपिक को हटाया नहीं जा रहा है। दोनों अधिकारी-कर्मचारी को जिले में खुलकर भ्रष्टाचार करने की छूट मिली हुई है। जिला पंचायत सदस्य तुलिका ने बताया कि अगर जल्द ही लिपिक रिलिव नहीं किया गया तो जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करें -कलेक्टर

समय-सीमा की बैठक सम्पन्न

बीजापुर/मूक पत्रिका

कलेक्टर संबित मिश्रा ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनदर्शन में प्राप्त सभी आवेदनों का समय-सीमा में त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए, अनावश्यक रूप से आवेदन लंबित न हो। इस दौरान मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजी पोर्टल एवं कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का समीक्षा करते हुऐ विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।बैठक में नियद नेल्लानार क्षेत्रों में सर्वे, सैचुरेशन शिविर की प्रगति ग्रामीणों सहित आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित परिवारों को प्रदाय की जाने वाली आवश्यक दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, आधारकार्ड, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि के बारे में विस्तृत समीक्षा किया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास, व्यक्तिगत शौचालय सहित सूदूर क्षेत्रों में संचालित विकास कार्यों की प्रगति के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।जिले में सीएसआर मद से प्राप्त नवीन 8 एम्बुलेंस सहित उपलब्ध सभी एम्बुलेंस को मरीजों के त्वरित ईलाज हेतु टोल फ्री नंबर जारी करने एवं उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। वन अधिकार पत्र हेतु प्राप्त आवेदनों का अनुभाग स्तर पर अनुशंसा पश्चात जिला स्तरीय समिति के बैठक जल्द आयोजित कर प्राप्त प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।सुशासन तिहारअंतर्गत प्राप्त आवेदनों/प्रकरणों का निराकरण करने संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन भी दिए।जिलास्तरीय नामजद अधिकारियों को आश्रम, पोटाकेबिन के निरीक्षण संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुऐ व्यवस्थाओं में व्यापक सुधार लाने को कहा गया।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर भूपेन्द्र अग्रवाल सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारीगण, समस्त अनुभाग के एसडीएम डिप्टी कलेक्टर, सीईओ जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय के सीएमओ उपस्थित थे।

दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन,अंदरूनी क्षेत्रों में बस परिचालन हेतु रूट चार्ट तैयार करने,ई-ऑफिस प्रणाली एवं जाति प्रमाण पत्र वितरण जैसे विभिन्न बिन्दुओं की हुई गहन समीक्षा

साप्ताहिक समय-सीमा की हुई बैठक, मुख्यालय में आम नागरिकों हेतु निशुल्क पौध वितरण केन्द्र स्थापित करने हेतु कलेक्टर ने दिए निर्देश

दंतेवाड़ा/मूक पत्रिका

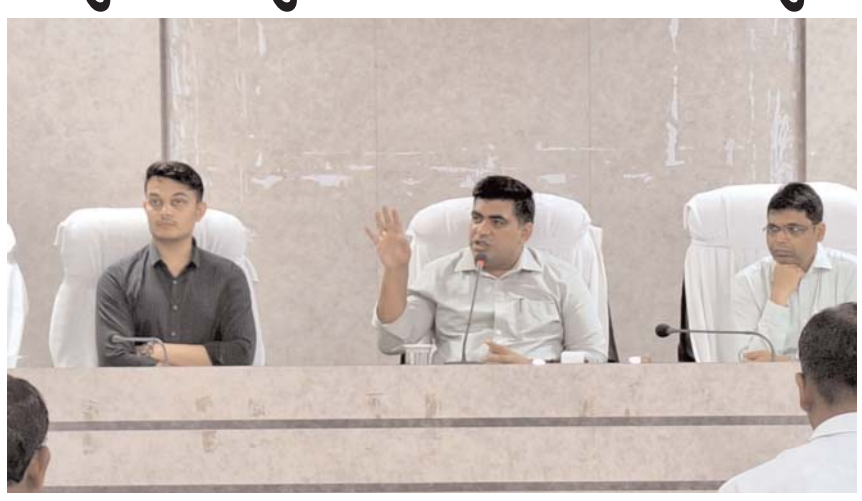

जिला कार्यालय के सभा कक्ष में बीते मंगलवार को समय सीमा बैठक कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में आहूत की गई थी। बैठक में कलेक्टर ने दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना,एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यालय में नागरिकों को निशुल्क पौध वितरण,नीति आयोग विकास सूचकांक के तहत संपूर्णता अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी कर्मचारियों को सम्मानित करने,अंदरूनी क्षेत्रों में बस परिचालन हेतु रूट चार्ट तैयार करने,जैसे विभिन्न बिन्दुओं के अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र वितरण में अद्यतन प्रगति,आश्रम छात्रावासों में नियमित निरीक्षण,ई -ऑफिस प्रणाली,नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु योजनाओं की संतृप्तिकरण पर भी विस्तृत दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बैठक में दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना को शासन की प्राथमिकता वाली फ्लैगशिप योजना बताते हुए कलेक्टर ने कहा कि इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में सीएमओ प्रभावी क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के अलावा अनुसूचित क्षेत्रों में देव स्थलों में पूजा करने वाले पुजारी, बैगा, गुनिया, माझी, चालकी भी पात्र होगें। अगर परिवार के पास आवासीय भूमि है तो भी वे लाभार्थी होगें। ऐसे आवेदक जो योजना के लिए पात्र है और पंजीकृत नहीं है वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते है। योजना के आवेदन पत्र ग्राम या नगर पंचायत के तहत प्राप्त किए जा सकेगें। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि इसके लिए पंजीयन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कर इसका लाभ पात्र हितग्राहियों को देना सुनिश्चित करें और योजना के तहत अद्यतन रिपोर्ट प्रति समय सीमा बैठक में चाही जाएगी। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने वन विभाग को निर्देश दिया कि मुख्यालय के सार्वजनिक स्थानों में निशुल्क पौध वितरण स्टॉल स्थापित करें ताकि आम नागरिक भी इस अभियान से जुड़कर अपनी सहभागिता दें। इसके लिए विभाग द्वारा पौधों के वितरण की घर पहुंच सेवा भी प्रदाय की जानी चाहिए। नीति आयोग विकास सूचकांक के अन्तर्गत संपूर्णता अभियान के परिप्रेक्ष्य में कृषि स्वास्थ्य,महिला बाल विकास, पशुधन विकास, विभाग द्वारा विगत महिने उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी कर्मचारियों हेतु सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सभी विभाग विकास सूचकांक से संबंधित डेटा प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगें। इसी प्रकार अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के निर्देशानुसार बस परिचालन हेतु रूट चार्ट तैयार करने का प्रस्ताव भेजने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्ताव में ऐसे अंदरूनी क्षेत्रों को प्राथमिकता देवें जहां सार्वजानिक आवागमन की साधन न के बराबर है। इसके अलावा बैठक में कलेक्टर ने पहचान दंतेवाड़ा के तहत जन्म, आधार और राशन कार्ड की साप्ताहिक प्रगति, आश्रम छात्रावासों में मूलभूत व्यवस्थाओं के नियमित निरीक्षण हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, छात्रों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण,नक्सल प्रभावित परिवारों के युवाओं हेतु रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रारंभ किए जाने, जाति प्रमाण पत्र बनाये जाने के आवेदनों पर की जा रही साप्ताहिक प्रगति पर भी विस्तारपूर्वक समीक्षा किया। बैठक में कलेक्टर ने ई-ऑफिस प्रणाली के तहत सर्व विभाग प्रमुखों और उनके अधीनस्थ स्टाफ को ई-ऑफिस प्रणाली के तहत संपूर्ण प्रशिक्षित होने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आगामी माह से सभी कार्यालयीन कार्यो जैसे फाइल, दस्तावेज और पत्राचार, नोटशीट इत्यादि ई-ऑफिस प्रणाली के तहत ही संपादित होगें। अतः सर्व विभाग ई-ऑफिस के तहत किसी भी प्रकार की समस्याएं आने पर अपने कर्मचारियों को जिला कार्यालय में भेज कर इसका समाधान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम सभी विभाग प्रायोगिक तौर पर फाइल तैयार कर इसे ई-ऑफिस प्रणाली की प्रक्रिया अनुसार जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें इसकी भी समीक्षा आगामी समय सीमा बैठक में ली जावेगी। राज्य शासन के निर्देशानुसार शासन के डिजिटलीकरण किए जाने के दिशा में अब जिले के सभी कार्यालयों में फाइलों दस्तावेजों और पत्राचार नोटशीट का प्रबंधन डिजिटल के माध्यम से किया जाएगा। जिससे शासकीय कार्य पारदर्शी प्रभावी और सुव्यवस्थित होगें और आम नागरिक को प्रभावी सेवाएं मिलेगी। इसके तहत कार्यालयीन कार्यो में फाइलों की ट्रैक रिपोर्टिंग जैसी सभी गतिविधियां ऑनलाइन किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा, अपर कलेक्टर राजेश पात्रे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

संपादकीय

जानलेवा पुल लोगों के जीवन कर रहे समाप्त

किसी भी हादसे का सबसे बड़ा सबक यह होना चाहिए कि वैसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए सभी स्तर पर हरसंभव उपाय किए जाएं। मगर ऐसा लगता है कि बार-बार के हादसों के बावजूद सरकारी तंत्र के लिए इस पर गौर करना कोई जरूरी काम नहीं है और उसकी नींद तभी खुलती है, जब किसी बड़े हादसे से लोगों के बीच उपजा आक्रोश तूल पकड़ने लगता है। गुजरात के वडोदरा में एक पुल ढह जाने और उससे हुए जानमाल के नुकसान की घटना सरकारी तंत्र की इसी व्यापक लापरवाही और संवेदनहीनता का सबूत है। गौरतलब है कि वडोदरा में आणंद और पादरा को जोड़ने वाले व्यस्त पुल का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इसकी चपेट में कई वाहन आए और टूटते पुल से महिसागर नदी में गिर गए। खबरों के मुताबिक, इसमें कम से कम सोलह लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए। इस घटना को भी किसी आम हादसे की तरह देखा जाएगा, मरने और घायल होने वालों के लिए मुआवजे की घोषणा और जांच का आश्वासन जारी कर दिया जाएगा। मगर आमतौर पर ऐसी घोषणाओं के बाद सरकारी रवैया कुछ ही दिन में फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट जाता है और शायद किसी अगले हादसे का इंतजार किया जाने लगता है। यह समझना मुश्किल है कि जिस पुल के जर्जर होने और कभी भी हादसे का शिकार होने की आशंका से जुड़ी खबरें आ चुकी थीं, उस पर यातायात को रोकने और अन्य सुरक्षा इंतजाम करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की गई। यह बेवजह नहीं है कि अब ऐसे सवाल तीखे रूप में उठाए जा रहे हैं कि गुजरात में इस तरह के खराब गुणवत्ता वाले जानलेवा पुल के बनने और भरभरा कर ढहने का सिरा सरकार के किन-किन महकमों और उसके कर्ता-धर्ता से जुड़ा है और इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। जिस राज्य के विकास को देश भर में उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है, वहां सिर्फ चालीस साल पहले बना पुल इस हालत में पहुंच जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसे लोगों की पड़ताल कर उन्हें कानून के कठघरे में खड़ा किया जाएगा? दरअसल, वडोदरा में पुल गिरने की घटना देश भर में ऐसे हादसों की महज एक कड़ी है। इससे पहले अक्तूबर, 2022 में गुजरात के ही मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना एक पुल नदी में गिर गया था, जिसमें एक सौ पैंतीस लोगों की जान चली गई थी। तब यह खबर आई थी कि सरकार ने सभी पुलों को मजबूती से जांचने और रखरखाव पुख्ता करने का दावा किया है। मगर पुल ढहने की ताजा घटना से सरकारी दावों की हकीकत एक बार फिर सामने आई है। आमतौर पर किसी भी पुल के बनने के वक्त ही उसकी कुल आयु और रखरखाव के बारे में बता दिया जाता है। अगर कोई पुल किन्हीं वजहों से जोखिम की हालत में होता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। ठोस तरीके से उसकी मरम्मत की जाती है या फिर उसका पुनर्निर्माण किया जाता है। विडंबना यह है कि वडोदरा के जर्जर पुल के जोखिम की आशंका जताए जाने के बावजूद कोई सावधानी नहीं बरती गई। अब सरकार को यह बताने की जरूरत है कि अगर आशंकाओं की जानबूझ कर अनदेखी नहीं की गई तो पुल की हालत के प्रति व्यापक लापरवाही की

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर कटाक्ष करते हुए एक बेहद गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी की है जिसको लेकर विवाद गहरा गया है। देखा जाये तो राजनीति में एक दूसरे की आलोचना करना या विचारों से असहमति जताना स्वाभाविक है, लेकिन जब यह टिप्पणी देश की विदेश नीति या प्रधानमंत्री की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी हो, तब यह सिर्फ आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसके राजनयिक प्रभाव भी हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भगवंत मान ने एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह 140 करोड़ लोगों वाले देश में नहीं रहते, बल्कि 10,000 की आबादी वाले देशों का दौरा करते हैं।

भगवंत मान के गैर-जिम्मेदाराना बयान से मोदी के कूटनीतिक प्रयासों पर फिर सकता है पानी

(नीरज कुमार दुबे)

इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है और अपने बयान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं की आलोचना वाली टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे 'गैरजिम्मेदाराना' करार दिया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर कटाक्ष करते हुए एक बेहद गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी की है जिसको लेकर विवाद गहरा गया है। देखा जाये तो राजनीति में एक दूसरे की आलोचना करना या विचारों से असहमति जताना स्वाभाविक है, लेकिन जब यह टिप्पणी देश की विदेश नीति या प्रधानमंत्री की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी हो, तब यह सिर्फ आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसके राजनयिक प्रभाव भी हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भगवंत मान ने एक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह 140 करोड़ लोगों वाले देश में नहीं रहते, बल्कि 10,000 की आबादी वाले देशों का दौरा करते हैं।

इस बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है और अपने बयान में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं की आलोचना वाली टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे 'गैरजिम्मेदाराना' करार दिया है। भगवंत मान का नाम लिए बिना मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ''राज्य के एक उच्च पदाधिकारी'' द्वारा की गई उन अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है, जिसमें मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों की अनदेखी की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने ग्लोबल साउथ के मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में राज्य के एक उच्च पदाधिकारी द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां देखी हैं। उन्होंने भगवंत मान की टिप्पणी पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये टिप्पणियां गैरजिम्मेदाराना और खेदजनक हैं तथा राज्य के किसी पदाधिकारी को शोभा नहीं देतीं। जायसवाल ने कहा, भारत सरकार मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करने वाली ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है।

देखा जाये तो भगवंत मान को समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं केवल द्विपक्षीय या बहुपक्षीय बैठकें नहीं होतीं, बल्कि वे भारत की वैश्विक स्थिति, रणनीतिक भागीदारी, निवेश संभावनाओं और सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर को मजबूत करने का माध्यम भी होती हैं। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों के दौरान दिये गये बयान और घोषणाएं भारत की विदेश नीति का चेहरा बनती हैं। ऐसे में जब देश का एक मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से इन यात्राओं की खिल्ली उड़ाता है, तो विदेशी सरकारें और कूटनीतिक संस्थान भारत की आंतरिक एकता, राजनीतिक परिपक्वता और स्थायित्व पर सवाल उठा सकते हैं।

भगवंत मान को समझना चाहिए कि विदेशी राष्ट्र भारत के भीतर के राजनीतिक मतभेदों को सावधानी से परखते हैं। भगवंत मान जैसे नेताओं की टिप्पणियां यह संकेत दे सकती हैं कि भारत की विदेश नीति पर विपक्षी दलों में विश्वास की कमी है। इससे भारत की राजनयिक विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है, विशेष रूप से तब, जब भारत ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने और ज्ञ20 जैसे मंचों पर मुखर भूमिका निभा रहा हो।

भगवंत मान को समझना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक देश में आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि नेता राष्ट्रीय मंचों और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर सार्वजनिक बयान देते समय राष्ट्रीय हितों की मर्यादा का ध्यान रखें। प्रधानमंत्री विदेश में न केवल सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि पूरे भारत का भी। ऐसे में उनके प्रयासों का उपहास उड़ाना अंततः देश के सामूहिक सम्मान को नुकसान पहुंचा सकता है। विदेशी मीडिया भारतीय नेताओं की ऐसी टिप्पणियों को उद्धृत करता है और कई बार उन्हें संदर्भ से बाहर पेश कर भारत को नुकसान पहुँचाया जाता है। भगवंत मान की टिप्पणी भी इसी श्रेणी में आ सकती है, जिससे भारत की विदेश नीति को लेकर भ्रम फैल सकता है। यह बात निवेशकों, रणनीतिक भागीदारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भारत के प्रति धारणा को भी प्रभावित कर सकती है।

भगवंत मान को समझना चाहिए कि भारत जैसी उभरती वैश्विक शक्ति के लिए यह आवश्यक है कि उसके आंतरिक राजनीतिक मतभेद अंतरराष्ट्रीय छवि को प्रभावित नहीं करें। विदेश यात्रा जैसे संवेदनशील विषयों पर राजनीतिक बयानबाज़ी भारत की एकजुटता पर सवाल खड़े कर सकती है। इससे यह संदेश जा सकता है कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रीय हितों पर राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देता है, जो किसी भी देश की छवि के लिए सकारात्मक संकेत नहीं होता।

हम आपको यह भी बता दें कि भगवंत मान ने पहली बार हल्के स्तर का बयान नहीं दिया है। इससे पहले भी वह विवादित बयान दे चुके हैं जिससे भारतीय कूटनीति के लिए असहज स्थिति बनी है। इंटरनेट पर खोजने पर ऐसी मीडिया रिपोर्टें मिलती हैं कि भगवंत मान ने अपने विदेश दौरों पर (विशेषकर जर्मनी और यूके) अप्रत्यक्ष रूप से भारत में लोकतंत्र के हालात पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कथित रूप से कहा था कि हम पंजाब में लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं जबकि अन्य राज्य दबाव में हैं। इससे विदेशी राजनयिक समुदाय में यह संदेश गया था कि भारत के भीतर लोकतांत्रिक स्थिति पर निर्वाचित नेता भी असहमति जताते हैं। देखा जाये तो यह भारत के विरुद्ध प्रचार को बल देता है।

बहरहाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर की गई टिप्पणी एक सीमित राजनीतिक फायदे की मंशा से की गई हो सकती है, लेकिन इसके प्रभाव व्यापक और बहुआयामी हो सकते हैं। लोकतंत्र में आलोचना आवश्यक है, लेकिन ऐसा राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलन बनाकर किया जाना चाहिए। कूटनीति केवल विदेश मंत्रालय की ही नहीं बल्कि सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी होती है इसलिए सभी को देश की वैश्विक प्रतिष्ठा के संरक्षण में अपनी भूमिका समझनी चाहिए और उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए। व्यक्तिगत बयानबाज़ी का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है यह बात भगवंत मान जैसे नेताओं को समझनी चाहिए।

खेलों में भारत को सुपर पावर बनाने की खास पहल

(अशोक कुमार)

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी)-2025 एक दूरदर्शी और परिवर्तनकारी पहल है, जो भारत को वैश्विक खेल शक्तियों की कतार में खड़ा करने वाली है। साल 2001 की नीति से आगे बढ़ते हुए एनएसपी-2025 खेलों को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में रखकर एक नया और व्यापक खाका पेश करती है, ताकि भारत खेलों की दुनिया में सुपर पावर बनने की दिशा में बढ़ सके। यह नीति खेलों को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शैक्षिक सुधार के उपकरण के तौर पर पुनर्परिभाषित करती है।

एनएसपी पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित एक मिशन-दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य प्रतिभाओं को पोषित करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, फिटनेस की संस्कृति को विकसित करना और हर स्तर पर समावेश को बढ़ावा देना है। इस नई नीति में शहरी व ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार, प्रशिक्षित कोचों की नियुक्ति और खेल विज्ञान को शामिल किया गया है।

यह नीति 'खेलो इंडिया' और 'लक्षित ओलंपिक पोडियम योजना' को मजबूत करेगी, जो खिलाड़ियों को प्रतियोगी मंच, वैश्विक प्रशिक्षण और आधुनिक संसाधन मुहैया कराएगी। यह नीति खेल को ऐसे पेशे के रूप में पेश करती है, जिसमें सटीकता, तैयारी व उद्देश्य की अहम भूमिका है। यह खेल को आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन मानती है। इसमें भारत को प्रमुख खेल आयोजनों का वैश्विक केंद्र बनाने का सपना देखा गया है, जिसमें ओलंपिक भी शामिल है।

नई खेल नीति समृद्ध खेल अर्थव्यवस्था के तहत खेल विज्ञान, खेल तकनीक, डिजिटल एनालिटिक्स और बुनियादी ढांचे के निर्माण में स्टार्टअप को बढ़ावा देगी। यह सार्वजनिक-निजी साझेदारी व सीएसआर के धन का उपयोग करेगी, साथ ही 'एडॉप्ट एन एथलीट' और 'वन कॉरपोरेट-वन स्पोर्ट' जैसी योजनाओं के माध्यम से निजी क्षेत्र को खिलाड़ियों व बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए प्रेरित करेगी। यह नीति पूंजी और रचनात्मकता, दोनों को साथ मिलाकर युवा पीढ़ी के लिए नए रोजगार के अवसरों को खोलने और खेल को एक मजबूत आर्थिक क्षेत्र में बदलने का काम करेगी।

नई नीति 'सभी के लिए खेल' के सिद्धांत को बढ़ावा देती है। भारतीय खेल धरोहर को संरक्षित करने के साथ ही यह इन्हें वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए कबड्डी, खो-खो, मल्लखंब और गतका जैसी पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने और इनको बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है। इसमें एक उल्लेखनीय पहल प्रवासी भारतीय को शामिल करना भी है। आज देश के लगभग 70 प्रतिशत शहरी मधुमेह और मोटापे की समस्या से ग्रस्त हैं। इस लिहाज से यह नीति इसका समाधान भी करती है। इसमें 'फिट वर्कप्लेस इंडेक्स' और 'स्कूल फिटनेस इंडेक्स' जैसे राष्ट्रीय सूचकांक शामिल हैं और '10,000 स्टेप्स ए डे' मुहिम को ध्यान में रखा गया है।

एनएसपी पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित एक मिशन-दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य प्रतिभाओं को पोषित करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, फिटनेस की संस्कृति को विकसित करना और हर स्तर पर समावेश को बढ़ावा देना है। इस नई नीति में शहरी व ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार, प्रशिक्षित कोचों की नियुक्ति और खेल विज्ञान को शामिल किया गया है।

यह खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों, जैसे अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया से प्रेरणा लेते हुए इनकी शिक्षा के महत्व पर जोर देती है। इन देशों के 35 से 50 प्रतिशत ओलंपिक पदक विजेता विश्वविद्यालयों से ही आते हैं। इस ढांचे के तहत स्कूल और विश्वविद्यालय खेलों को पेशेवर रूप में पेश करते हैं। इस नीति के तहत सभी शिक्षण संस्थान खेलों में छात्रवृत्तियां देंगे, बुनियादी ढांचे, खेल विज्ञान और कोचिंग का विकास करेंगे, ताकि संस्थानों में ऐसा तंत्र बन सके, जो अच्छे खिलाड़ियों को पहचान कर उनके समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर पाए।

एनएसपी-2025 सिर्फ नीति नहीं, राष्ट्रीय मिशन है। इसकी सफलता सटीक क्रियान्वयन, पारदर्शिता के अलावा सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थान व समुदाय के बीच निरंतर सहयोग पर निर्भर करेगी। लगभग डेढ़ अरब आबादी वाले भारत के लिए वह समय आ गया है कि हम अपनी क्षमता को पदकों में और अपनी भावना को उद्देश्य में बदलें। एनएसपी-2025 के साथ भारत अंतरराष्ट्रीय खेलों में केवल भाग लेने के लिए नहीं, बल्कि पदक प्राप्त करने के लिए तैयार होगा। (लेखक कुलपति, हरियाणा खेल विश्वविद्यालय हैं। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

गरीबों का जीवन गरिमामय बनाती राष्ट्रीय योजनाएं

भारत में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार सिर्फ संख्या की वृद्धि नहीं है, बल्कि नीतिगत दृष्टिकोण में भी एक गहरा बदलाव दर्शाता है। पहले जहां ये कल्याणकारी योजनाएं दिखावटी या चुनावी भाषणों तक सीमित समझी जाती थीं, वहीं अब उनको डाटा आधारित, कानूनी रूप से समर्थित व संस्थागत रूप से प्रमाणित ढांचे में समाहित किया गया है। इस बदलाव से गांवों-गरीबों का 'सिस्टम' के प्रति भरोसा जाग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंत्योदय और समावेशी विकास की यह नीति समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने की दिशा में बड़ा बदलाव है। यह एक ऐसा 'विजन' है, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी अब सिर्फ राजनीतिक लाभ का जरिया न बनकर तरक्की की कतार में शामिल हो रहे हैं।

(नवनीत सहगल)

भारत में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीते एक दशक में जो बदलाव आया है, उसे लगातार अंतरराष्ट्रीय मान्यताएं मिल रही हैं। बीते दिनों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा जारी किए गए आंकड़े इस बदलाव की औपचारिक पुष्टि करते हैं। साल 2015 में जहां भारत की महज 19 फीसदी जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में माना जाता था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 64.3 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, यानी करीब 94 करोड़ भारतीय अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यह न केवल राष्ट्रीय, बल्कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी एक उल्लेखनीय छलांग है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार सिर्फ संख्या की वृद्धि नहीं है, बल्कि नीतिगत दृष्टिकोण में भी एक गहरा बदलाव दर्शाता है। पहले जहां ये कल्याणकारी योजनाएं दिखावटी या चुनावी भाषणों तक सीमित समझी जाती थीं, वहीं अब उनको डाटा आधारित, कानूनी रूप से समर्थित व संस्थागत रूप से प्रमाणित ढांचे में समाहित किया गया है। इस बदलाव से गांवों-गरीबों का 'सिस्टम' के प्रति भरोसा जाग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंत्योदय और समावेशी विकास की यह नीति समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्त करने की दिशा में बड़ा बदलाव है। यह एक ऐसा 'विजन' है, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी अब सिर्फ राजनीतिक लाभ का जरिया न बनकर तरक्की की कतार में शामिल हो रहे हैं।

दरअसल, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की संकल्पना पर आधारित योजनाओं से बीते 10 वर्षों में यह स्पष्ट हुआ है कि जन-कल्याण सिर्फ सरकारी जुमला नहीं है, बल्कि यह शासन का प्राथमिक जिम्मेदारी है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलता यह रही है कि उसने लोक-कल्याणकारी योजनाओं को 'डिजिटल ट्रांसफर आधारित न्याय' में बदला। 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' के माध्यम से इस दौरान 44 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे गए। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, बल्कि सरकारी योजनाओं में लोगों का विश्वास भी बहाल हुआ। सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से आयुष्मान भारत योजना तो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। अब तक छह करोड़ से अधिक अस्पतालों में भर्ती रोगियों का मुफ्त इलाज और 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमा सुरक्षा देना यह साबित करता है कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अभिजात्य वर्ग की सुविधा से निकालकर आम नागरिक का अधिकार बना दिया है। जहां अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाएं सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं भारत ने गरीब से गरीब नागरिक को गंभीर रोगों से लड़ने की शक्ति दी है।

सामाजिक सुरक्षा की दिशा में 'कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी 2020' भी एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है। यह न केवल संगठित क्षेत्र को, बल्कि गिग इकोनॉमी और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के मार्ग खोलता है। एक आकलन के अनुसार, फूड डिलीवरी, कैब ड्राइविंग, फ्रीलांसिंग जैसे कार्यों में लगे गिग कर्मचारियों की संख्या 2030 तक 2.35 करोड़ हो जाएगी। उनके लिए सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रस्ताव भारत के बदलते श्रम परिदृश्य की समझ को दर्शाता है।

इसी तरह, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, अटल पेंशन योजना, किसान मानधन योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी योजनाएं वृद्ध नागरिकों के लिए समाज में सम्मान के साथ जीवन जीने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर रही हैं।

आईएलओ का सुझाव है कि सामाजिक सुरक्षा केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न होकर जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी होनी चाहिए। ऐसे में, हर घर जल योजना ने करोड़ों घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ने चार करोड़ से अधिक घरों का निर्माण करवाया। सौभाग्य योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं ने सामाजिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य को आर्थिक संरक्षण व गरिमा में परिवर्तित कर दिया है।

आईएलओ की मान्यता केवल वैश्विक तमगा नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि योजनाएं तभी प्रभावी होती हैं, जब वे नागरिकों के जीवन में प्रवेश करती हैं। (लेखक चेयरमैन, प्रसार भारती) (ये लेखक के अपने विचार हैं)

फर्जी वन अधिकार पट्टों का खुलासा, शासकीय भूमि पर कब्जे से ग्रामीणों में रोष

रसूखदारों पर कूटरच्ना से पट्टा बनवाने का आरोप, आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा

कांकेर/मूक पत्रिका

जिला कांकेर के चारामा विकासखंड अंतर्गत ग्राम मयाना (प.ह.नं. 15) में शासकीय चरागाह और वनभूमि पर फर्जी तरीके से वन अधिकार पट्टा जारी किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को दर्जनों ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जांच की मांग की।ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने ग्राम सभा और पंचायत की अनुमति के बिना कूटरचना कर वन पट्टा हासिल कर लिया है। इससे गांव में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और चरागाह के लिए भूमि नहीं बची है। मामला ग्राम मयाना के खसरा नंबर 1, 2, 3 और 4 से जुड़ा है, जिनमें जलाशय, भराव क्षेत्र और छोटे-बड़े जंगल शामिल हैं। ग्रामीणों के अनुसार इन भूमियों का उपयोग वर्षों से पशुओं की चराई के लिए होता रहा है। लेकिन हाल में प्रियांशु पिता सुरेश, प्रतिभा और प्रिंसी सहित अन्य के नाम पर 2.60 हेक्टेयर (ख.नं. 2)

और 2.00 हेक्टेयर (ख.नं. 3) भूमि पर फर्जी पट्टा बनवाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इन फर्जी पट्टों का इस्तेमाल किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने और धान खरीदी केंद्र में बिक्री के लिए किया जा रहा है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी में आदिवासी विकास विभाग, कांकेर के सहायक आयुक्त एवं जन सूचना अधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक आ.वि./ वन अधि/सु.का.अधि/1017/2025 दिनांक 01.07.2025 के जरिए बताया कि खसरा नं. 1, 2, 3, 4 में किसी भी हितग्राही को वन अधिकार पट्टा जारी नहीं किया गया है। गांव के सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि इन फर्जी पट्टों को रद्द कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही प्रशासन से यह भी अपेक्षा जताई है कि भविष्य में ग्राम सभा की अनुमति को अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, जिससे इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।वन अधिकार कानून का उद्देश्य आदिवासी और वनवासी समुदाय को अधिकार देना है, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग कर शासकीय जमीन पर कब्जा किया जाता है, तो इससे ग्रामीणों के हक प्रभावित होते हैं और शासन-प्रशासन की पारदर्शिता पर भी सवाल उठते हैं। ग्राम मयाना का यह मामला प्रशासन के लिए एक चेतावनी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

बाढ़ आपदा से निपटने जिला प्रशासन तैयार, 17 जुलाई को शिवनाथ नदी, अमोरा घाट पर आयोजित होगी मॉकड्रिल

जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा बाढ़ बचाव अभ्यास

बेमेतरा/मूक पत्रिका

संभावित बाढ़ आपदा से निपटने एवं बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा और परीक्षण के लिए बेमेतरा जिले में 17 जुलाई 2025 को बाढ़ बचाव मॉकड्रिल का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास प्रातः 8:00 बजे से शिवनाथ नदी के तट, अमोरा घाट, बेमेतरा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी संबंधित विभागों एवं अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

उपरोक्त मॉकड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में प्रशासनिक तत्परता, समन्वय, राहत एवं बचाव कार्यों की दक्षता का आकलन करना है। इस अवसर पर नगर सेना, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस, पंचायत, लोक निर्माण, विद्युत, जल संसाधन, शिक्षा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के अमले

की भी सहभागिता रहेगी। जिला कार्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार, मॉकड्रिल के दौरान जिले के समस्त वरिष्ठ अधिकारी एवं विभाग प्रमुख मौके पर उपस्थित रहेंगे, जिससे वास्तविक स्थिति के अनुरूप उनकी जिम्मेदारियों का परीक्षण किया जा सके। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल और आपसी समन्वय कितना प्रभावी रहता है। मॉकड्रिल के सफल आयोजन हेतु जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया की इस अभ्यास में सभी अधिकारियों को निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

सरकार बिजली बिल बढ़ोतरी अविलंब वापस ले-शिवसेना

कांकेर /मूक पत्रिका

शिवसेना, महिलासेना कांकेर द्वारा बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर कांकेर कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। महिलासेना के कार्यकर्ता लीना साहू त्रिवेणी साहू भारती शर्मा संध्या ने बताया कि सरकार पहले गैस सिलेंडर की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी किया गया। और अब बिजली उपभोक्ताओं के बिल में बढ़ोतरी कर प्रदेश की जनता की कमर तोड़ रखी है। प्रदेश के भाजपा सरकार प्रदेश की जनता को छलने का काम कर रही है। और पहले ही महंगाई से पीड़ित है ऐसे में महंगाई से राहत देने के बजाय बिजली की दर में वृद्धि करना आम जनता पर और बोझ डालने जैसे काम रही है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता महेश वासुदेव दुबे ने कहा हाल ही में बिजली बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है जिसमें आम जनता को भारी आर्थिक परेशानी होगी। हमारा क्षेत्र कांकेर जिला एक गरीब, मध्यम वर्ग, व पिछड़ा क्षेत्र है और इस वृद्धि से हमारे क्षेत्र के लिए अपने घरों का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। कई परिवार 4 के लिए बिजली का बिल उनके मासिक खर्च का 20 एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस वृद्धि से उनका बचत पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। बिजली बिल वृद्धि एक गंभीर समस्या है। बढ़ती बिजली दरों ने लोगों की आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर देगी। बिजली के दाम बढ़ने से आम जनता त्राहि त्राहि कर रही है शिवसेना नेता ने आगे कहा बिजली उत्पादन हेतु प्रदेश के अंदर कोयला, पानी, मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है उसके बाद भी प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा विद्युत दर वृद्धिप्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा विद्युत दर वृद्धि कर प्रदेश की गरीब जनता के ऊपर एक और भार डाला जा रहा है जबकि देश के अन्य हिस्सों में छत्तीसगढ़ से कोयला जाता है उसके बाद भी वहां विद्युत दर कम है प्रदेश में गरीबी की मार झेल रही आम जनता को विद्युत दर बढ़ाने के कारण बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ेगा।

आदिवासियों का पुनर्वास क्यों नहीं करना चाहती है सरकार -डॉ. संदीप पाठक, प्रदेश प्रभारी

छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को अडानी को देने आमादा साय सरकार–मुकेश अहलावत, प्रदेश सह प्रभारी,क्क छग

रायपुर/मूक पत्रिका

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉ. संदीप पाठक ने कांकेर के भानुप्रतापपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्य की साय सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आदिवासियों के हितों की रक्षा करने में सरकार विफ्ल साबित हुई है। और जैसा सरकार बोल रही है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलमुक्त कर देंगें पर सरकार जवाब दे की जो लोग सलवा जुडूम विस्थापित हुए थे वे लोग आज कहां हैं? पुनर्वास के तहत जो कैंप में गए थे उनकी वस्तु स्थिति क्या है? सरकार स्पष्ट करें! जो गांव वीरान पड़े हैं वो लोग कहां गए और अगर उनका पुनर्वास नहीं हो पाया है तो सरकार ने क्या कदम उठाए? निश्चित ही सरकार की मंशा जंगल को किसी और के

हाथ में देने की है,क्योंकि अगर पुनर्वास नहीं होते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि किसी भी प्रकार के ग्राम सभा का आयोजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलवा जुडूम आंदोलन के दौरान विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास मामले में स्थिति चिंताजनक है और सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को इसका जवाब दे।भाजपा अपने डेढ़ साल के कार्यकाल में ही नाकाम दिख रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सह प्रभारी, उप नेता विपक्ष,दिल्ली,मुकेश अहलावत ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जल जंगल ज़मीन को साय सरकार उद्योगपतियों के हवाले करना चाहती है। राज्य में अडानी के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहें हैं और मुख्यमंत्री ÷एक पेड़ मां के नाम÷ का दिखावा कर रही है। सरकार आदिवासियों के रोजगार की व्यवस्था आज तक नहीं कर पायी है. पुनर्वास की व्यवस्था करने में सरकार फेल रही है। आदिवासियों के लिए अच्छे स्कूलों की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। राज्य सरकार आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया क्यों नहीं कर पा रही है,आज भी अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो उनका इलाज दंतेवाड़ा बीजापुर में कराना पड़ता है। पाँचवी अनुसूची होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगता है उद्योगपतियों से विष्णुदेव साय जी ने पूरे छत्तीसगढ़ को उजाड़ने का ठेका ले लिया है प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने कहा कि सरकार पन विद्युत परियोजना के प्रभावित 53 गांव में ग्राम सभा क्यों नहीं करवा रही है। विस्थापित आदिवासी परिवारों को आज भी बुनियादी पहचान, भूमि, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर तत्काल अमल हो, हथियार की रिकवरी और पुनर्वास योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए। विस्थापित आदिवासियों को जल जंगल जमीन पर अधिकार मिलना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू, प्रदेश महासचिव वदूद आलम, प्रदेश संगठन महामंत्री जसबीर सिंग चावला, प्रदेश महासचिव (सोशल मीडिया, मीडिया प्रभारी, मुख्य प्रवक्ता) सूरज उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तम जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु चंद्रा,प्रदेश संगठन मंत्री तेजेंद्र तोड़ेकर , प्रदेश सह सचिव के. ज्योति,रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अज़ीम खान, रायपुर लोकसभा महासचिव प्रदुमन शर्मा,रायपुर लोकसभा उपाध्यक्ष इमरान खान,प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य कांकेर देवलाल नरेटी,प्रदेश अध्यक्ष (आदिवासी विंग) मेहर सिंह वट्टी,प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम चंद्राकर,प्रदेश संगठन प्रभारी संतराम सलाम, कांकेर लोकसभा अध्यक्ष हरेश चक्रधारी,महिला प्रदेश अध्यक्ष मिथलेश बघेल, प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा, नारायणपुर जिलाध्यक्ष नरेंद्र नाग,बालोद जिलाध्यक्ष बालक साहू, कांकेर जिला मीडिया प्रभारी रविंद्र शोरी, शिव शर्मा सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु काउंसलिंग उपस्थित 15 से 18 जुलाई तक गुढियारी रायपुर में आयोजित होगी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन छ.ग. नया रायपुर के आदेशानुसार मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालयों को कक्षा 9वीं (सत्र 2025-26) में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की वर्गवार प्रतीक्षा सूची विभाग की वेबसाईट https://eklavya.cg.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। प्रतीक्षा सूची में दर्शित विद्यार्थी निर्धारित तिथि एवं समय में काउंसलिंग फॉर्म भर कर अनिवार्य दस्तावेजो सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें। काउंसलिंग की तिथि व समय का वर्गवार विवरण इस प्रकार है।

15 जुलाई 2025: अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (क्क्ङ्क्रञ्जत्र) बालक। 16 जुलाई 2025: अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (क्क्ङ्क्रञ्जत्र) बालिका। 17 जुलाई 2025: अनुसूचित जाति बालक/बालिका। 18 जुलाई 2025: अन्य पिछड़ा वर्ग बालक/बालिका। 18 जुलाई 2025: सामान्य वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बालक/बालिका। काउंसलिंग स्थल प्रयास कन्या आवासीय विघायल गुढ़ियारी जिला रायपुर।

प्रत्येक दिन काउंसलिंग का समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक निर्धारित है। सभी विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि पर दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

खरीफसीजन 2025 में उर्वरक वितरण पर कलेक्टर सख्त - जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष गठित

- कालाबाजारी, जमाखोरी और तस्करी रोकने छह सदस्यीय निगरानी दल तैनात

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन मे खरीफ2025 मौसम के लिए किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में उर्वरक की कालाबाजारी, तस्करी, डायवर्शन, जमाखोरी एवं अनियमित बिक्री को रोकने हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) का गठन किया गया है। यह कंट्रोल रूम जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक-67, उप संचालक कृषि, संयुक्त कलेक्टोरेट भवन बेमेतरा में स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष की निगरानी हेतु छह सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें सहायक संचालक कृषि डॉ. श्याम लाल साहू को नियंत्रण कक्ष प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिनसे मोबाइल नंबर 6260907138 पर संपर्क किया जा सकता है। इनके सहयोग हेतु वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी दिनेश कुमार धुर्वे (साजा) को नियंत्रण कक्ष सहायक नियुक्त किया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 8717872585 है। इसी प्रकार वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी देवानंद देवांगन (बेरला) को भी नियंत्रण कक्ष सहायक बनाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 7999972258 है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी (नवागढ़) को भी सहायक के रूप में दायित्व सौंपा गया है, जिनसे मोबाइल नंबर 9977253850 पर संपर्क किया जा सकता है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी दीपक कुमार साहू (उर्वरक शाखा प्रभारी) को नियंत्रण कक्ष उप सहायक के रूप में रखा गया है, जिनका मोबाइल नंबर 8889443493 है। वहीं वाहन चालक कुलेश्वर सिन्हा को भी इस टीम में शामिल किया गया है, जिनका संपर्क नंबर 8224918363 है। यह टीम जिले में उर्वरक से संबंधित शिकायतों, गुप्त सूचनाओं, अनियमित गतिविधियों की निगरानी करेगी और ऐसी किसी भी जानकारी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेगी। यह कार्य स्ग्रष्टह्र 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही, शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु यह टीम समय-समय पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी। किसानों से अपील की गई है कि यदि उर्वरक की आपूर्ति, कीमत, या गुणवत्ता को लेकर कोई समस्या या अनियमितता हो तो वे उक्त अधिकारियों से सीधे संपर्क कर जानकारी साझा करें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।

महुआ शराब की बिक्री करने वाला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कांकेर /मूक पत्रिका

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 14.07.2025 को जरिये मुखबीर अघनगर कंकेर में आबकारी की सूचना मिलने पर सउनि सोमेन्द्र सिंह हमराह स्टाफमय विवेचना किट के रवाना होकर मुखबीर सूचना तस्दीकर पर गवाहों के सांथ अघननगर पहुंचकर हमराह स्टाफ व गवाहों के सांथ मुखबीर के बताये स्थान को घेरा बंदी कर रेड कार्यवाही किये शराब खरीदने वाले पुलिस को आता देखकर ईधर उधर भाग गये मौके पर एक व्यक्ति मिला जिसके पास दो पंळाच लीटर वाला जरीकेन एवं दो लीटर वाला थम्सअप बॉटल मिला जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम अखिलेश कुमार शर्मा पिता जागेश्वर शर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी अघन नगर कंकेर का रहने वाला बताया जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराया गया एवं सहमती से तलाशी लेने पर उसके पास दो पंडाच-पांच लीटर वाला जरीकेन में लगभग 10

लीटर एवं एवं दो लीटर वाला थम्सअप बॉटल में 402 लीटर कुल बल्क 12 लीटर एक लीटर की किमत 100 रूपया कुल किमत 1200 रूपये एवं जप्ती रकम 300 रूपये कुल जुमला रकम 1500 रूपये मिला जिसे मौके पर गवाहों के समक्ष माप कर मौके पर शील बंद कर पंचनामा तैयार किया गया। जिसे दिनांक 14.07.2025 को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है। उक्त महुआ शराब रखने एवं बेचने के संबंध में अखिलेश कुमार शर्मा को धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस देकर शराब रखने एवं विक्रय करने वैध दस्तावेज पेश करने के संबंध में हिदायत दिया गया। जिसके संबंध मेंअखिलेश कुमार शर्मा द्वारा कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस नहीं होना लिखित में दिये। आरोपी का कृत्य धारा- 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से गवाहों के समक्ष आरोपी अखिलेश कुमार शर्मा पिता जागेश्वर शर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी अघन नगर कंकेर को दिनांक 14.07.2025 को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर देहाती नालसी अप.क्र. 00/25 धारा-34(2) आब. एक्ट कायम कर बाद थाना आकर असल नंबरी अपराध क्र. 202/25 धारा-34(2) आब.एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान श्रीमान उ.म.नि. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आई. के. एलिसेला (भा.पु.से.) उ.ब. कांकेर के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश सिन्हा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कांकेर मोहसीन खान के मार्गदर्शन में आरोपी अखिलेश कुमार शर्मा पिता जागेश्वर शर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी अघन नगर कंकेर के विरूद्ध पर्याप्त 26 साक्ष्य पाये जाने से रिमाण्ड फार्म तैयार कर माननीय न्यायालय कांकेर पेश किया गया है।

डेढ़ साल में भाजपा सरकार ने चौथी बार बढ़ाये बिजली के दाम, जनता की जेब में सरकार कर रही डकैती- लालू राठौर

खाद के नाम पर भाजपा किसानों को ठगने का काम कर रही है- लालू राठौर

बीजापुर /मूक पत्रिका

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर लूटने का काम प्रदेश की भाजपा सरकार ने शुरू किया है। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, गैर घरेलू बिजली की दर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है। उन्होंने कहा सर्वाधिक बढ़ोतरी कृषि पंप के बिजली के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करके की गई है। छत्तीसगढ़ के किसान इस सरकार की दुर्भावना और उपेक्षा के चलते पहले ही खाद, बीज और बिजली कटौती से परेशान हैं, अब कृषि पंप में बिजली की दर बढाकर कर

भाजपा सरकार किसानों की कमर तोड़ रही है।

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर ने आगे कहा कि इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जनता को लूटने के तरह-तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। 2003 से 2018 तक भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने हर साल बिजली के दामों में वृद्धि की। 2003 में छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 रुपए 30 पैसे के दर पर बिजली मिला करती थी, जिसे 15 साल के कुशासन के बाद रमनसिंह के समय ही 6 रुपए 40 पैसे तक बढ़ाया गया, जिसे चुनावी वर्ष 2018 में मात्र 20 पैसे घटकर 6 रुपया 20 पैसे किया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में पूरे 5 साल का नेट वृद्धि देखें तो मात्र दो पैसे का था, जो ऐतिहासिक तौर पर सबसे न्यूनतम था।अपने प्रेस विज्ञप्ति में लालू राठौर ने आगे कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने बिजली के घाटे को पाटते हुए बिजली बिल ऑफ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 65 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 3240 करोड रुपए के सब्सिडी देकर बहुत बड़ी राहत दी थी। किसानों को 5 एचपी तक निशुल्क बिजली दिया, बीपीएल उपभोक्ताओं को 40 यूनिट तक मुक्त बिजली दी गई। अस्पतालों, उद्योगों को सब्सिडाइज्ड दर पर बिजली देकर राहत पहुंचाया। भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश भर में बिजली की कटौती शुरू हो गई और कीमत लगातार बढ़ाई जाने लगी है। उन्होंने कहा ÷कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेचा जा रहा है?÷लालू राठौर ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारी एसी का मजा लूट रहे, कई सरकारी विभाग बिजली का बकाया बिल जमा नहीं कर रहें, सरकारी उपक्रमों और सरकार के चहेतों का करोड़ों का बिजली बिल का भुगतान लंबित है, उसकी वसूली भी भाजपा सरकार जनता से कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते हैं बिजली का उत्पादन लागत बढा है, कोयले पर ग्रीन टैक्स चार गुना अधिक बढ़ा दिए, रेलवे का माल भाड़ा अधिक वसूल रहे हैं, थर्मल पॉवरप्लांट को अडानी की कंपनी से महंगे दर पर कोयला खरीदने बाध्य किया जा रहा है, डीजल पर सेंट्रल एक्साइज बढ़ाए जाने से परिवहन में और फायर के लिए उपयोग होने वाले डीजल की लागत बढ़ी है जिसकी भरपाई भी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाकर किया जा रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर ने आगे कहा कि प्रदेश भर से अनाप-शनाप बिजली बिल आने की शिकायत लगातार आ रही है, स्मार्ट मीटर के नाम पर अधिक बिल उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है, अब तो जनता को लूटने के लिए अडानी की कंपनी का प्रीपेड मीटर भी लगाने की तैयारी है, भाजपा सरकार पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही है, अघोषित कटौती रोज-रोज जारी है, ऊपर से सरकार ने बिजली के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी करके जनता की जेब में डकैती डाला है। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार के ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध करती है, सरकार के इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी।

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने किया विकास कार्यों का भूमिपूजन

- 27.72 लाख की लागत से स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को मिलेगी नई दिशा

जगदलपुर /मूक पत्रिका

आम जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने वाले सांसद महेश कश्यप ने बीते मंगलवार को ग्राम छोटेकवाली, कवालीकला एवं माँझीगुड़ा में 27.72 लाख की लागत से निर्मित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमिपूजन कर किया।यह विकास कार्य स्वच्छता एवं जनस्वास्थ्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करेगा। भूमिपूजन कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणजनों एवं गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। सांसद कश्यप ने बताया कि ÷विकास कार्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता निरंतर जारी है। हमारा प्रयास है कि हर गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुँचे और जनता को बेहतर जीवन मिले।÷ इस अवसर पर ग्रामीणजनों ने सांसद का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में क्षेत्र में लगातार सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है।

जल संचय और संरक्षण के कार्यों को दी जाए प्राथमिकता-कलेक्टर हरिस एस

- समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

जगदलपुर -/मूक पत्रिका

कलेक्टर हरिस एस ने कहा कि जल संरक्षण हेतु रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सभी शासकीय भवन, स्कूल, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन, समिति भवन में सुविधा उपलब्ध करवाना है। इसके लिए विभागीय बजट व जनभागीदारी के सहयोग से किया जाना है। हर ब्लॉक में 100-100 घरों में जल संरक्षण हेतु चिन्हांकित कर काम करना है। नरेगा के तहत भी जल संचय और संरक्षण के कार्यो को प्राथमिकता दी जाए। कलेक्टर हरिस ने मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में उक्त निर्देश दिए।

बैठक में पंचायत एडवांटेच इंडेक्स 2.0 में एंट्री करवाने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही जन शिकायत, पीजी पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन के प्रकरणों पर निर्धारित समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम किश्त प्राप्त उपरांत आवास निर्माण की प्रगति को दिसम्बर माह तक पूरा करें। निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रति माह कार्ययोजना अनुसार काम को पूर्ण करवाएं। एनआरएलएम की महिला स्व-सहायता समूहों को बैकिंग सुविधा दिलवाने हेतु चर्चा किया गया, किसी बैंक के द्वारा ऋण प्रकरण को कार्यवाही नहीं करने पर संबंधित बैंक से शासकीय राशि हटाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला खनिज व्यास संस्थान अंतर्गत स्वीकृत देवगुड़ी निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा किए वर्ष 2022-23 के प्लिंथ स्तर पर रहने वाले काम को निरस्त करने का प्रस्ताव देने के निर्देश दिए। साथ ही अन्य विकास कार्यो की जनपदवार, विभागवार प्रगति की संज्ञान लिए। कलेक्टर ने खाद्य विभाग से संबंधित अधिकारियों से खाद्यान्न भण्डारण की स्थिति की जानकारी ली, उन्होंने गोदाम में हमालों की दिक्कत पर संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न भण्डारण हेतु राशि जमा की स्थिति तथा चना, शक्कर, गुड, नमक का भण्डारण स्थिति का संज्ञान लिया। धान खरीदी केंद्र से धान उठाव के साथ ही लेखा मिलान करवाकर चावल को जमा करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनपद और नगरीय निकाय क्षेत्र से राशन कार्डो से सदस्यों का नाम हटाने और निरस्त राशन कार्ड की स्थिति की समीक्षा किए। पांच माह से राशन नहीं उठाने वालो की तथा राशन दुकानों के खाद्य सामानों की उपलब्धता का जांच करने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। कृषि विभाग के अधिकारी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नवीन पंजीयन के वारिसान प्रकरणों के लंबित पंजीयन का जल्द निराकरण करवाने के निर्देश दिए। एग्री स्टैक पंजीयन कार्य को जल्द पूर्ण करने कहा, उन्होंने कहा कि धान खरीदी हेतु को किसानों का राजस्व भूमि का रिकॉर्ड के आधार पर एग्री स्टैक में पंजीयन करवाना अनिवार्य है। पिछले साल जिन्होंने धान बेचा उनको जरूर एग्री स्टैक पर पंजीयन करवाना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने स्कूल जतन कार्यो के संबंध में चर्चा करते हुए एसडीएम के रिपोर्ट के आधार पर खराब काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा। शाला त्यागी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु कार्य में आवश्यक प्रयास करने तथा नव-प्रवेशित बच्चों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए। स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र निर्माण व निवास पत्र निर्माण की प्रगति की समीक्षा किए सभी बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनवाने कहा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र और उचित मूल्य की दुकानों की जर्जर भवन का चिंहाकन कर जानकारी देंने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से आयुष्मान कार्ड के लिए नगरीय क्षेत्र के वार्डो में शिविर लगाने तथा वाय वंदना योजना कार्ड के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैम्प कर कार्ड बनवाने के लिए निर्देशित किया।

मावा पुलिस केतुल अभियान के तहत गंगालूर स्कूल में जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

बीजापुर/मूक पत्रिका

जिला बीजापुर पुलिस द्वारा संचालित ÷मावा पुलिस केतुल÷ अभियान के अंतर्गत गंगालूर हायर सेकेंडरी विद्यालय में एक विस्तृत जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों में सुरक्षा, सतर्कता, संवैधानिक अधिकारों एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।

कार्यक्रम में विनीत कुमार साहू, उप पुलिस अधीक्षक (डीआरजी)गिरीश तिवारी टीआई गंगालूर,अवध सिंहा, यातायात शाखा अधिकारी उपस्थित रहे।साथ ही साइबर सेल, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सखी सेंटर की प्रतिनिधियों द्वारा भी विषय आधारित जागरूकता प्रस्तुतियाँ दी गई।उप पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार साहू ने छात्रों को नक्सल उन्मूलन अभियान, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति, तथा नक्सली प्रोपेगेंडा की यथार्थता के विषय में अत्यंत सरल एवं प्रभावी ढंग से समझाया। उन्होंने आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति की उपयोगिता बताते हुए यह भी कहा जो युवा भटक गए हैं, उनके लिए सरकार द्वारा एक सम्मानजनक वापसी का रास्ता उपलब्ध है। समाज उन्हें फ्रि से अपनाने को तैयार है। आप सब देश की मुख्यधारा से जुड़कर उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।÷

फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी सोशल साइट्स पर अनजान लिंक, नकली प्रोफाइल या लालच4 देने वाले ऑफ्र से सावधान रहें। कोई भी निजी जानकारी ड्ढ ओटीपी, पासवर्ड, बैंक डिटेल ड्ढ किसी से साझा न करें*।÷यातायात शाखा से अवध सिंहा ने विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा, हेलमेट की अनिवार्यता, और कम उम्र में वाहन न चलाने के खतरे के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम की अन्य वक्ता :मीना वर्मा (सखी सेंटर) और पदमा बघेल (महिला एवं बाल विकास विभाग) द्वारा महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, ÷गुड टच ड्ढ बैड टच÷, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर शोषण, तथा क्क्ष्टस्ह्ल ष्ह्ल व महिला संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी गई। अंत में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी की। विजेताओं को सम्मानित कर उनके उत्साह को बढ़ाया गया।÷मावा पुलिस केतु÷ अभियान का उद्देश्य है – छात्र-छात्राओं और आम नागरिकों को न केवल कानून की जानकारी देना, बल्कि उनके मन से भय हटाकर विश्वास का माहौल बनाना। यह अभियान शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण की त्रिवेणी को आगे बढ़ाने का प्रयास है।

गायों के संरक्षण के लिए जिले में चलेगा गौ सेवा संकल्प अभियान

- कलेक्टर ने 90 प्लस अभियान अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर दिया जोर
- साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में की विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा

मुंगेली -/मूक पत्रिका

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में गायों के संरक्षण के लिए गौ सेवा संकल्प अभियान की शुरूआत की गई। कलेक्टर ने इस अभियान की शुरूआत करते हुए कहा कि गायों को बचाने, गायों की सेवा, सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा यह संवेदनशील पहल किया जा रहा है। उन्होंने गौ सेवा संकल्प अभियान के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि गाय माता के समान है, उसके प्रति सम्मान का भाव जागृत करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने लोगों को गाय गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कलेक्टर ने गाय के प्रति करुणा एवं जागरूकता फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गौवंश के सड़क पर होने से दुर्घटना की आशंका रहती है। सड़क से गायों को हटाएं और इसके लिए लोगों को जागरूक करें, ताकि सड़क दुर्घटना कम हो। उन्होंने सेवा भावना का दृष्टिकोण विकसित करते हुए गायों की सुरक्षा के लिए ईमानदार प्रयास करने और इस पहल को जनभागीदारी तथा जनअभियान के रूप में लेने व गॉवों में चौपाल लगाकर गौ सेवा के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने प्रोत्साहित किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गाय का धार्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व है, गाय हमारी संस्कृति का हिस्सा है। उन्होंने अभियान के महत्व बताते हुए कहा कि इसे मिशन के रूप में ले और संवेदनशीलता से गौ सेवा करें। जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पाण्डेय ने गौ सेवा संकल्प अभियान के कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि बेसहारा गायों को आश्रय प्रदान करना और उनकी देखभाल करना सबसे बड़ी सेवा है। इस मुहिम में हम सभी को शामिल होना चाहिए। कलेक्टर ने 90 प्लस परीक्षा परिणाम की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए कम प्रगति वाले चिन्हित 90 स्कूलों में शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को स्कूलों का लगातार निरीक्षण करने और मॉडल स्कूल बनाने बेहतर प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बच्चों और शिक्षकों से संवाद करने और बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने प्रोत्साहित किया। कलेक्टर ने महिला बाल विभाग की महतारी वंदन योजनांतर्गत एफआर.एस. के संबंध में जानकारी ली और बेहतर प्रगति के लिए सराहना की। खाद-बीज की समस्या के संबंध में जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को खाद-बीज की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ई-ऑफ्सि के सुचारू क्रियान्वयन पर जोर दिया। इसी प्रकार उन्होंने आयुष्मान कार्ड, जनदर्शन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों, फ्लैगशिप योजनाएं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, ई-कोर्ट के लंबित प्रकरणों, उज्ज्वला योजना जैसे फ्लैगशिप योजनाओं में लक्ष्य अनुरूप आवश्यक प्रगति लाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सही मायनों में सुशासन है और यह हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने विभागीय योजनाओं में भी बेहतर रैंक लाने प्रेरित किया। कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के गरिमामय आयोजन एवं तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्टेडियम की रंगाई, पुताई, नालियों की साफ-सफाई, गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अचानकमार टाईगर रिजर्व क्षेत्र के बच्चों को स्वतंत्रता दिवस पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल करें। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए चिन्हांकित करने के निर्देश दिए।

आदिवासी शिक्षक दम्पति पर की गई निलंबन कार्यवाही असंवैधानिक ,आर. टी.आई. से खुलासा - बीरेंद्र नेताम जिला संयोजक

मूक पत्रिका/कोंडागांव -कलेक्टर कोंडागांव एवं जिला शिक्षा अधिकारी कोंडागांव के द्वारा सुनियोजित तरीके से एक ही मामले पर अलग अलग मात्र 8 घंटे के अंदर नोटिस के साथ ही जितनी तत्परता से निलंबन की कार्यवाही की गई है,उससे यह निश्चित रूप से प्रतीत हो रहा है कि राजनैतिक आकाओं की दबाव में असंवैधानिक रूप से कार्यवाही हुई है।

प्रभारी कन्या छात्रावास कोंडागाव अधीक्षिका नीता मंडावी व पति नरसिंह मंडावी (शिक्षक)एवं जिला अध्यक्ष गवर्नमेंट एम्प्लाईज वेलफेयर एसोशिएशन जिला कोंडागांव के ऊपर की गई एकतरफा कार्यवाही असंवैधानिक है। प्रशासन निलंबन कर नियम कानून की अनदेखी कर बहाली करना भूल गया है ।

सोशल मीडिया से ज्ञात हुआ है कि शासन की अड़यल रवैया से विवस होकर शिक्षक दम्पति आमरण अनशन के लिए बाध्य हो रहे हैं।

प्रशासन अनूसूचित क्षेत्र में लागू होने वाले नियमों को ध्यान में रखकर तत्काल संज्ञान लेकर बहाली करे अन्यथा आदिवासी समाज, सामाजिक संगठन एवं कर्मचारी संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा।

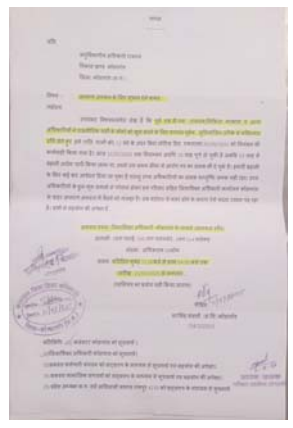

''सामान्य प्रशासन विभाग छ ग शासन ने समय समय पर अनु जाति जनजाति के प्रति कार्यवाही पर नरमी बरतने की आदेश है फिर भी जिला स्तर के अधिकारियों ने मनमानी पूर्वक आदिवासी समाज के शिक्षक को निलंबित कर दिया जिसे बहाल करने में कोताही बरती जा रही हैं ,मान्यता प्राप्त संगठन के जिलाध्यक्ष के साथ प्रशासन व शिक्षा विभाग का रवैया ऐसी है तो आम शिक्षको के कैसे करती होंगी जगजाहिर हैं।

अगर निलंबित को तत्काल बहाल नहीं करेगी तो पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन की जाएगी ,संगठन पीड़ित परिवार के साथ है÷ :- कृष्णकुमार नवरंग प्रांताध्यक्ष 7898154376

अपने कमरे में विवाहित पति-पत्नी एक साथ रह सकते है इससे परिवार को और समाज को कोई आपत्ति नही होती, इसे विवाहित लोग ही समझ सकते है। पहली बार ऐसे चापलूस अधिकारी को देख रहा हु जिसे अप्पति है । इनकी समझ अल्प बुद्धि की ओर इशारा करता है। यह अविवाहित एस.डी. एम.के समझ से बाहर है। कार्यवाही करने में इतनी तेजी अन्य मांग पत्रो और शिकायतो में में भी दिखाया जाता तो कोंडागाँव में आज तक बहुत तरक्की हुई होती।निलंबन के 10 माह बीत जाने के बाद भी इन अधिकारियों के द्वारा बहाली नही करना इनकी कार्य कुशलता पर प्रश्न चिन्ह है।

÷अधिकारियों को सिर्फशासन के निर्देशो का पालन करना है बल्कि यहां नेताओ के इशारों से शिक्षक कर्मचारीयो पर कार्यवाही करने के साथ ,पार्टी नेताओ की चापलूसी करना जरूरी है। बेवजह परेशान करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही किया जाए ताकि भविष्य में किसी कर्मचारी बेवजह परेशान न हो। कोंडागांव जिला के शासकीय कर्मचारीयो पर किसी भी प्रकार की समस्या आएगी, छग सर्व आदिवासी समाज कोंडागांव 4230 उनके संरक्षण के लिए आगे आयेगी जरूरत पड़ेगी तो सड़क की लड़ाई लड़ेगी।'÷ - पनकु राम नेताम जिला अध्यक्ष

छग सर्व आदिवासी समाज कोंडागांव 4230 93404 29185

शासन से मान्यता प्राप्त संगठन के जिला अध्यक्ष नरसिंह मंडावी एवं उनके पत्नी पर बेतुका, तर्कहीन आरोप लगाकर कार्यवाही किया गया है, सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी अनुसार अधिक्षिका के कमरे में परिवार सहित रह सकते है, पति -पत्नी को अलग रहने के लिए कोई दिशा निर्देश नही है। जो कारवाही किया गया है वह गलत है आरोपी अधिकारी पर कार्यवाही किया जाए । तत्काल बहाली आदेश जारी कर निलंबन को कार्यावधि मानकर संस्था में कार्य करने के लिए आदेश जारी किए जाए,हम पीड़ित परिवार के साथ है'' हेमन्त ध्रुव ,संभागीय अध्यक्ष बस्तर संभाग छग।

कानून व्यवस्था को मजबूती देने में कोटवारों की भूमिका महत्वपूर्ण - कलेक्टर

- कोटवार प्रशिक्षण का गॉव में करें बेहतर उपयोग - पुलिस अधीक्षक
- ''पहल'' बदलाव की शुरुआत सुरक्षा के साथ कोटवारों के लिए आयोजित 15 दिवसीय प्रशिक्षण का हुआ समापन

मुंगेली -/मूक पत्रिका

रिजर्व पुलिस लाइन मुंगेली में ''पहल'' बदलाव की शुरुआत सुरक्षा के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत कोटवारों के लिए 01 जुलाई से 15 जुलाई तक आयोजित 15 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर कुन्दन कुमार और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल शामिल हुए। कलेक्टर ने कोटवारों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि कोटवार प्रशासन की रीढ़ हैं। जिले में कहीं भी अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने कानून व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोटवारों की महत्वपूर्ण सूचना से कोई बड़ी घटना टल सकती है, इसलिए अपने कार्यों को गंभीरता से करना है। अपने-अपने गॉवों में नशा मुक्ति के लिए विशेष रूप से कार्य करें, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें, पलायन को रोकने जिले में ही रोजगार के बेहतर विकल्प दिलाने का प्रयास करें। स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति, बाल विवाह और अन्य कुप्रथाओं की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दें। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य के लिए कोटवारों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सभी कोटवारों को पहचान कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे वे महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं कार्यों के लिए आसानी से कलेक्टर एवं एसपी सहित अन्य अधिकारियों से मिल सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कोटवार मोहन दास के गाने की सराहना की।

एसपी भोजराम पटेल ने कहा कि यह प्रशिक्षण आपके सम्पूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल है। कोटवारों के इस प्रशिक्षण से उनके कर्तव्य शक्ति एवं अधिकारों का बोध होता है। कोटवार प्रशासन के प्रतिनिधि होते है इसलिए गांव में किसी भी घटना की स्थिति में सजग एवं तत्पर होना है। अपराध नियंत्रण, आमलोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोटवारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी कोटवार प्रशिक्षण में मिले ज्ञान का अपने गांव में जाकर बेहतर उपयोग करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा ने कहा कि कोटवारों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए इस प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, इससे निश्चित रूप से सभी कोटवारों के जीवन की दिशा बदलेगी। कोटवार पुलिस और प्रशासन के सहयोगी के रूप में हमेशा खड़े रहेंगे। कार्यक्रम में सभी कोटवारों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के अपने अनुभवों को बताया।

शाला प्रवेश उत्सव में बच्चों की रंगारंग प्रस्तुतियां, शिक्षा व संस्कार पर दिया गया विशेष बल

मूक पत्रिका/सूरजपुर/भैयाथान (बरौधी):-- विकासखंड भैयाथान के ग्राम पंचायत बरौधी स्थित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय परिसर में मंगलवार को शाला प्रवेश उत्सव धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। स्वागत गीत से आरंभ हुआ कार्यक्रम धीरे-धीरे रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में तब्दील हो गया और स्कूल परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। छात्र-छात्राओं ने नृत्य, कविता और गीतों के माध्यम से अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मंच पर बच्चों का आत्मविश्वास और प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपसरपंच दिनेश प्रताप सिंह और विशिष्ट अतिथि पत्रकार मोहन प्रताप सिंह रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम सरपंच विनोद कुमार किंडो ने की। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य किशुन राम व ज्ञान प्रसाद सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। प्रधानपाठक संजय कुमार भारती और रज्ञीन सिंह ने बच्चों, अभिभावकों और ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा

कि स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि मूल्य, संस्कार और चरित्र निर्माण का प्रथम केंद्र है। उन्होंने बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन, आदर और मेहनत को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी। मुख्य अतिथियों ने भी अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ही जीवन की दिशा और दशा तय करती है। शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपने गुरुओं का सम्मान करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें।

शिक्षकगण आनंद प्रकाश गुप्ता, मीना राजवाड़े, वर्षा चौधरी, कविता दिवाकर और सुमित्रा राजवाड़े की सराहनीय सहभागिता से यह आयोजन और भी व्यवस्थित और प्रेरणादायक बन सका। कार्यक्रम के अंत में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। अतिथियों और शिक्षकों ने मिलकर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यह पहल ग्रामीणों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम रहा। शिक्षिका प्रियंका पटेल के सौजन्य से विद्यार्थियों के लिए मध्यान्ह भोजन की विशेष व्यवस्था की गई, जिसने आयोजन को और गरिमामयी बना दिया। कार्यक्रम का मंच संचालन शिक्षिका मीना राजवाड़े ने प्रभावशाली ढंग से किया।

ठेकेदारों पर कार्रवाई से नहीं छिपेगा सिस्टम का असली दोष - महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़

- जांच रिपोर्ट के बाद भी सवालों के घेरे में जिम्मेदार अफ्सर और चापलूस समर्थक

सूरजपुर/मूक पत्रिका

राज्यभर की आंगनबाड़ियों में घटिया सामग्रियों की आपूर्ति मामले में छह एजेंसियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। राज्य स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने यह कार्रवाई की है। सरकार इसे पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस की नीति की मिसाल बता रही है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बरकरार है क्या केवल ठेकेदारों को दोषी ठहराकर प्रशासन अपने कर्तव्य से बच सकता है?

जांच रिपोर्ट में जिन सामग्रियों की गुणवत्ता खराब पाई गई, वे बिना अधिकारियों की संलिप्तता और अनुमति के सिस्टम में कैसे पारित हो गई? लाखों-करोड़ों की खरीदी के बाद भी निगरानी, निरीक्षण और स्वीकृति की जिम्मेदारी जिन अफ्सरों पर थी, उनके खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्रवाई अधूरी है और शायद सिर्फ दिखावे के लिए है।

पत्रकारों पर उंगलियां, चापलूसों की जयजयकार- इस मामले में एक और शर्मनाक पहलू यह सामने आया कि जब कुछ निर्भीक पत्रकारों ने इस पूरे घोटाले को उजागर किया, तो उन्हें अपमान और आरोपों का सामना करना पड़ा।

जिन्होंने जनता के हक के लिए कलम चलाई, उन पर कुछ नेताओं और तथाकथित मंत्री समर्थकों ने वसूलीबाज, कमीना, कांग्रेसी पत्रकार, गद्दार जैसे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो पत्रकारों को कुत्ता कहने तक की जुबानी गिरावट दिखाई।

ये आरोप ऐसे लोगों ने लगाए जो खुद को संगठन का हिस्सा मानते हैं या मंत्रियों के करीबी कहकर भ्रम फैलाते हैं।

अब सवाल यह उठता है क्या इन परिक्रमा छाप नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी कोई अनुशासनात्मक या संगठनात्मक कार्रवाई होगी, या फिर इन्हें आगे चलकर इनाम के तौर पर पद देकर नवाजा जाएगा?

सवाल वही, अफ्सर क्यों बचे?

0 क्या अफ्सरों को क्लीनचिट देना ही जांच का उद्देश्य था?

0 क्या ठेकेदार बिना अफ्सरों की मिलीभगत के इतनी बड़ी मात्रा में घटिया सामग्री सप्लाई कर सकते थे?

0 अगर आपूर्तिकर्ता दोषी हैं तो खरीद प्रक्रिया पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी क्यों निर्दोष माने जा रहे हैं?

सूत्रों के मुताबिक, ब्लैकलिस्ट की गई एजेंसियों को फिर से अलग-अलग नामों से प्रवेश न मिल जाए, इसके लिए कोई ठोस सुरक्षा तंत्र अब तक स्थापित नहीं किया गया है। इससे साफ है कि एक हाथ से कार्रवाई और दूसरे से ढील की दोहरी नीति चल रही है।

अब जनता पूछ रही है, कार्रवाई अधूरी क्यों?- यह स्पष्ट है कि विभाग ने सिर्फ सप्लायर्स पर कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपाने का प्रयास किया है, जबकि इस पूरे भ्रष्ट तंत्र की जड़ में वे अधिकारी और सत्तासीन समर्थक हैं जिनकी मिलीभगत के बिना कोई गड़बड़ी संभव नहीं।

अगर सरकार सच में पारदर्शिता की बात करती है, तो उसे पत्रकारों को अपमानित करने वालों, दोषी अधिकारियों, और गोपनीय संरक्षण प्राप्त एजेंसियों के खिलाफ भी उतनी ही सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।

विधायक और मंत्री की भूमिका पर भी उठने लगे सवाल- क्षेत्रीय विधायक (भटगांव) और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से अब जनता और मीडिया यह सवाल कर रहे हैं कि क्या वे इन अपमानजनक बयानों पर चुप्पी साधे रहेंगे?

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा की बैठक संपन्न

सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली से कार्य पर दिया जोर

कोंडागांव/मूक पत्रिका

कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना की अध्यक्षता में बीते मंगलवार को साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें खाद-बीज की उपलब्धता, राशन वितरण सहित स्वास्थ्य एवं शिक्षा एवं अन्य विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिले में ई आफिस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि सभी शासकीय फाइलें एवं दस्तावेज ई-ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत करें।

बैठक में कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी से तीन माह के लिए राशन वितरण की जानकारी लेते हुए शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत कार्यों के प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि आवास निर्माण के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि कोई भी हितग्राही आवास निर्माण हेतु प्राप्त राशि का दुरूपयोग न करे, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने आवास निर्माण में लापरवाही बरतने एवं राशि के दुरूपयोग की स्थिति आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने जिले के विद्यालयों में शिक्षकों के उपस्थिति की जानकारी ली और कहा कि लंबे समय से अनुपस्थित या मद्यपान करने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्यवाही करें। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि एफआरएस कार्य में प्रगति लाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने आंनगबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु सभी सीईओ जनपद को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने जिले के सभी आंगनबाड़ी के बच्चों को विभाग द्वारा प्राप्त ड्रेस उपलब्ध कराने और निर्धारित ड्रेस में ही बच्चों की उपस्थिति केन्द्रों में सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने जिला अस्पताल की मरम्मत कार्य के प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने जिले में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सीट स्कैन, एक्सरे मशीन सहित अन्य उपकरणों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिले के अस्पतालों में सभी आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण कार्यशील होना चाहए। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी अस्पताल निर्धारित समय में बंद नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के लिए काउंसलिंग करने पर जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों के प्रगति की भी समीक्षा की और कार्य में प्रगति लाने हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। कलेक्टर ने जिले में कृषि कार्य के दौरान समुचित खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए। साथ ही फील्ड पर कृषि केन्द्रों में खाद की नियमित जांच सुनिश्चित करने को भी कहा। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ अविनाश भोई, अपर कलेक्टर चित्रकांत चार्ली ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के नगदरहित उपचार हेतु ऑनलाईन पोर्टल का प्रशिक्षण आयोजित

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार बर्मन ने बताया कि जिला अस्पताल के सभा कक्ष में सड़क दुर्घटनाओं से पीडितों को नगद रहित उपचार की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाईन पोर्टल में आईआरएडी/ईडीएआर का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में डी.आर.एम एन.आई.सी श्रीमती साधना गुप्ता द्वारा पोर्टल के तकनीकी पहलुओं, कार्यप्रणाली और उपयोग की विस्तृत जानकारी दी गई । प्रशिक्षण के दौरान समस्त चिकित्सालयो को योजनांतर्गत अपने चिकित्सालय का पंजीयन करने के निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण में जिले के समस्त आयुष्मान भारत योजनांतर्गत पंजीकृत चिकित्सालय के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रशिक्षण में आयुष्मान भारत के डीपीसी आशीष कुमार त्रिपाठी, अंकित ताम्रकार सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर दिखे शिक्षक की भूमिका में विद्यार्थियों से पूछे सवाल, शैक्षणिक संस्थानों किया औचक निरीक्षण

ग्राम जर्वे (च), खोखरा एवं पोड़ीशंकर के स्कूल, आंगनबाड़ी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हनीडीह का किया निरीक्षण

शैक्षणिक संस्थानों की जमीनी हकीकत से रूबरू हुए कलेक्टर, दिए आवश्यक सुधार के निर्देश

कनकपुर स्कूल परिसर में जलभराव देख नाराज हुए कलेक्टर, सचिव को नोटिस जारी करने के निर्देश

मूक पत्रिका/जांजगीर-चांपा - कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने मंगलवार को बलौदा, नवागढ़ एवं बम्हनीडीह विकासखंड के शासकीय स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों, बच्चों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, परिसर की स्वच्छता एवं पोषण आहार की उपलब्धता की बारीकी से जांच की और आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने स्कूल परिसर आंगनबाड़ी भवन एवं स्वास्थ्य केंद्र में साफ-सफाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की और साफ-सफाई कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान जांजगीर एसडीएम सुब्रत प्रधान, चांपा एसडीएम सुमित बघेल, डीएमसी आर के तिवारी सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्टर महोबे ने शासकीय प्राथमिक स्कूल जर्वे में शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाए जा रहे विषयों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने स्कूली छात्र-छात्राओं से विभिन्न विषयों के संबंध में चर्चा की और ब्लैक बोर्ड पर भी उन्होंने विभिन्न प्रश्न करते हुए विद्यार्थियों से जवाब लिए। गणित विषय में कमजोर बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जर्वे (च) में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की दर्ज संख्या के अनुसार कम उपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आंगनबाड़ी सहायिका को बच्चों को तत्काल उपस्थित कराने कहा। साथ ही संबंधित सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को मूलभूत ज्ञान नहीं होने पर उन्होंने पठन-पाठन की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन देने और परिसर की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खोखरा में निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने शिक्षकों से पढ़ाए जा रहे विषयों की जानकारी ली और छात्रों से सीधा संवाद कर उनसे सवाल किए। उन्होंने भाषा ज्ञान एवं गणित विषय के गहन अध्ययन पर बल देते हुए विषयवार शिक्षको की वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही रसोई कक्ष की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। शासकीय नवीन प्राथमिक शाला, आनंद नगर पोड़ीशंकर में निरीक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के संबंध में बातचीत की। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खेल-खेल में सिखाने, बच्चों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कनकपुर प्राथमिक शाला परिसर में पानी भराव की स्थिति को लेकर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तत्काल ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने और पानी निकासी के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने एबीसीडी, फल-सब्जियों के नाम जैसी बुनियादी जानकारी सभी बच्चों को हो, इस पर जोर दिया और महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित किया कि वे अभिभावकों को प्रेरित कर अधिक से अधिक बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रवेश दिलाएं। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र समय पर खुलने और कार्यकर्ता सहायिका को समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं एवं किशोरियो व नवजात बच्चों को नियमित जांच के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री महोबे ने साफतौर पर कहा कि शिक्षा, स्वच्छता और पोषण तीनों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हनीडीह में जाना मरीजों का हाल- कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हनीडीह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में चल रही विभिन्न गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने दवाई वितरण केंद्र, एक्स-रे रूम, लेबर रूम सहित अन्य वार्डों का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होनें मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए बेहतर उपचार करने के डाक्टरों को निर्देश दिए।

विधानसभा में गूंजेगा मेडिकल कैशलेस की मांग का मुद्दा

छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ की मेहनत लाई रंग, विधायकों ने लगाए प्रश्न

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है, जिसमें प्रदेश के बहुत से मुद्दे उठाए जाएंगे और उन पर चर्चा और बहस होगी। इसी प्रयास में अपनी मांगों को पूर्ण करवाने के लिए छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारी ने पूरे प्रदेश में एक मुहिम चला कर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विधायकों को मेडिकल कैशलेस लागू करने हेतु ज्ञापन सौंपा था, जिसमें संगठन को बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है कि छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारी एवं उनके परिवारों की मांग मेडिकल कैशलेस सदन में गूंजेगी वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के द्वारा तारांकित प्रश्न लगाया है दूसरी ओर प्रदेश के एक ओर विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े के द्वारा तारांकित एवं द्वारकाधीश यादव विधायक खल्लारी के द्वारा भी विधानसभा में शासकीय कर्मचारी के लिए मेडिकल कैशलेस सुविधा का प्रावधान लागू करने का समय आदि पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष उषा चंद्राकर ने यह भी बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत से भी संगठन के सदस्यों की मुलाकात हुई और उन्होंने भी आश्वत किया है कि कर्मचारियों और उनके सदस्यों से जुड़ी इस मांग को सदन में जरूर उठाया जाएगा।

यहां यह जानना आवश्यक है कि मेडिकल कैशलेस की मांग क्यों है ? पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अपने-अपने परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए मेडिकल कैशलेस सुविधा की मांग कर रहे हैं प्रदेश संरक्षक राकेश सिंह का कहना है कि कर्मचारियों को मेडिकल प्रतिपूर्ति की सुविधा तो प्राप्त है मगर प्रतिपूर्ति को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन और मुश्किल कार्य कर्मचारियों को अपना इलाज करवाने हेतु सर्वप्रथम हॉस्पिटल का खर्च स्वयं वहन करना होता है कभी-कभी बीमारी गंभीर होने पर पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है जिसमें कर्मचारियों के द्वारा अपनी संपूर्ण जमा पूंजी या बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़े गए पैसे एवं जमीन तक को बेचना पड़ता है। वहीं देखने में यह भी आता है कि कर्मचारी अपने एवं अपने सदस्य के इलाज के लिए साहूकारों से ब्याज में भी पैसा प्राप्त करते हैं अपने रिश्तेदारों के सामने या अपने सहपाठियों के सामने उन्हें हाथ फैलाना पड़ता है और जब मेडिकल रीइंबर्समेंट की बारी आती है तो उनके पूरे इलाज के खर्च का उन्हें मात्र 60त्न ही राशि प्राप्त होती है जिसमें ऑफिस खर्च काट के कर्मचारियों को 40 से 50त्न राशि ही प्राप्त होती है और यह राशि को मिलने का समय कम से कम 6 मा का होता है कभी-कभी ज्यादा राशि होने पर यह फाइल प्रदेश से पास की जाती है ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को यह राशि प्राप्त ही नहीं होती और कर्मचारी दर-दर भटकता रहता है। इस समस्या को देखते हुए कुछ कर्मचारियों ने मिलकर छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ का निर्माण किया जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक शासकीय कर्मचारी एवं उनके सदस्यों के इलाज के लिए मेडिकल कैशलेस की मांग शासन से की, संगठन का स्पष्ट कहना है की कर्मचारी और उसके सदस्य का जितना भी इलाज हो उसका सीधा-सीधा खर्च शासन वहां करने अस्पताल में कर्मचारी और उसके सदस्यों को पैसे के लिए किसी भी प्रकार का सहयोग न लेना पड़े जिस प्रकार भिलाई स्टील प्लांट एस ई सीसीएल के कर्मचारियों को कार्ड के माध्यम से जो सुविधा दी जाती है इस प्रकार अपने राज्य और देश में इलाज के लिए हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की जाए यह कार्ड किसी भी प्रकार से आयुष्मान सुविधा से ना जुड़ा हो, बल्कि कर्मचारियों को इसका लाभ सीधा-सीधा प्राप्त हो पिछले ही माह डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने वहां के कर्मचारियों को 20 लाख रुपए का मेडिकल कैशलेस की घोषणा की दूसरी ओर गुजरात में भी डबल इंजन की सरकार ने वहां के कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस की घोषणा की आपको बता दें कि देश के कई राज्य केरल उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल कैशलेस की सुविधा वहां के कर्मचारियों को प्राप्त होती है तो फिर हम छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को इस प्रकार की सुविधा प्राप्त क्यों नहीं हो रही इन सब बातों को संगठन के द्वारा प्रत्येक विधायक पक्ष के नेता एवं विपक्ष के नेताओं से भी चर्चा की गई जिसमें सभी के द्वारा यह अस्वस्थ किया गया कि आपकी यह मांग जायज है और जल्द से जल्द हम आपकी मांग को पूरा करेंगे वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी यह आश्वस्त किया की आने वाले कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा प्राप्त होने वाला है अब संगठन के द्वारा अटकल यह लगाई जा रही है कि शायद विधानसभा सत्र समाप्ति के बाद कर्मचारियों को उनकी लंबित मांग मेडिकल कैशलेस जीवन रेखा कहीं जाने वाली यह मांग की घोषणा जल्द से जल्द मुख्यमंत्री द्वारा की जा सकती है वही प्रदेश के कुछ कर्मचारियों से भी चर्चा की गई, जिसमें कर्मचारियों के द्वारा इस मांग को जल्द से जल्द पूरी करने के लिए शासन से मांग की गई

छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिध मंडल ने किया नव पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी का अभिनंदन

शक्ति/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ सर्व शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिध मंडल ने नव पदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती कुमुदनी बाघ द्विवेदी से सौजन्य भेंट कर उन्हें शॉल और पुष्पगुच्छ भेंट कर मिठाई खिलाकर उन्हें सम्मानित किया। तथा जिले में शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराया । जी पी एफपास बुक संधारण , सर्विस बुक संधारण , व्यायाम शिक्षक जिनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त हो चुका है और अभी तक नियमिति करण नहीं हो पाया है उनका शीघ्र नियमिति करण किए जाने तथा सभी विकासखंड में परामर्श दात्रि समिति की बैठक रखे जाने का सुझाव जिला शिक्षा अधिकारी को दिया । जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने शीघ्र पहल करने की बात कही। आज डीईओ से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी , प्रदेश उपाध्यक्ष परस राम निषाद,प्रदेश संयुक्त सचिव चंद्रभान कश्यप, जिला अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा , जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सरिता मनहर , ब्लॉक अध्यक्ष डभरा अर्जुन खूंटे , राज रोशन ब्लॉक अध्यक्ष,अमर दास मानिकपुरी, बाबू लाल सिदार, पुष्पेंद्र सिदार, नरेंद्र सिदार , सुरेश पटेल, रामदयाल कर्ष, रमेश कंवर , रामेश्वर कंवर, दिलबहार यादव, वेद प्रकाश जायसवाल, चरन सिंह, भूषण बरेठ , राज कुमार अग्रवाल, चुंबक श्रीवास , भास्करन नायर , शैलेन्द्र सिदार , अमित पटेल, पवन मरावी आदि उपस्थित थे।

छात्रों से धान बिनवाने का वीडियो वायरल, शिक्षक गोपी कुमार तिवारी निलंबित

बम्हनीडीह विकासखंड के सिलादेही स्कूल का है मामला

नेतागिरी करने वाले शिक्षकों पर भी हो कार्यवाही

मूक पत्रिका/ जांजगीर-चांपा - जिले के शासकीय प्राथमिक शाला सिलादेही में छात्रों से धान बिनवाने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक शिक्षक (एल. बी.) गोपी कुमार तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद की गई जिसमें शिक्षक तिवारी द्वारा कक्षा चौथी के बच्चों से धान बिनवाने की पुष्टि हुई। यह मामला विकासखंड बम्हनीडीह के अंतर्गत आता है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1) के तहत अनुशासनहीनता और कदाचार की श्रेणी में आता है। निलंबन के दौरान तिवारी का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बम्हनीडीह नियत किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश की प्रतिलिपि प्रेषित कर त्वरित अनुपालन का निर्देश दिया है। यह कदम शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और छात्रों की गरिमा की रक्षा की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

नेतागिरी करने वाले शिक्षकों पर भी हो कार्यवाही- गौरतलब है कि शिक्षा में सदियों से चला आ रहा ये भ्रष्टाचार का एक छोटा उदाहरण है, शिक्षा विभाग की छबि सुधारने के लिए शिक्षक नेताओं जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रहता पर कार्यवाही भी होना चाहिए ताकि उन्हें अपने मूल कार्य (शिक्षकीय) के बारे में ज्ञात हो सके। जिले में ऐसे कई शिक्षक नेता हैं (हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है) जो शिक्षक तो हैं, मगर कभी बच्चों को पढ़ाया नहीं।

बसपा ने विभिन्न मांगों लेकर राज्यपाल को सौपा ज्ञापन

रायपुर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ प्रदेश बसपा ने छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचलों में आम जनता एवं किसानों को अनेक प्रकार की जनहितकारी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण निम्नलिखित समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी हैंरू .

खाद व बीज की भारी किल्लत- किसानों को बुआई के मौसम में आवश्यक खाद एवं बीज नहीं मिल रहे हैं। सरकारी वितरण प्रणाली ठप हैए जिससे किसान बिचैलियों से महंगे और नकली खादए बीजए खरीदने को विवश हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही हैए बल्कि कृषि उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

शिक्षा व्यवस्था की बदहाली- युक्तियुक्तकरण के तहत हजारों शासकीय स्कूलों को बंद करनाए एवं शिक्षकों की भारी कमीए निजी स्कूलों को बढ़ावा देना छण्गण् के गरीब मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना है। अधिकांश विद्यालयों में अब तक बच्चों को पाठ्यपुस्तकें और गणवेश नहीं मिले हैंए जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। ग्राम सुंदरकेरा जनपद पंचायत अभनपुरए जिला रायपुर में उच्च माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन 2018 में हुआ था लेकिन स्वीकृत व्यख्याता पद अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर स्थिति- ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है। जीवन रक्षक दवाईयाँ उपलब्ध नहीं हैं। प्रसव सेवाएंए टीकाकरण और सामान्य उपचार भी समय पर नहीं मिल पा रहा हैंए जिससे आम जनता में विशेषकर महिलाएं और बच्चे अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं।

बिजली व सड़क की गंभीर स्थिति- कई गांवों में ट्रांसफॉर्मर महीनों से जले पड़े हैंए और विद्युत आपूर्ति ठप है। सड़कों की हालत बद से बद्तर है कई गांवों का जिला मुख्यालय से सम्पर्क कट गया है। जिससे स्कूलए अस्पताल हाट.बाजार पहुंचना कठिन हो गया है।

जनहित की अन्य समस्याएं

1 . बेरोजगारी चरम पर है युवा वर्ग हताश हैं।

2 . निराश्रित व वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन दिव्यांग पेंशन समय पर नहीं मिल पाना।

3 . शुद्ध पेयजल की गम्भीर समस्या के कारण महामारी की सम्भावना।

4 . सरकारी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार एवं भेद.भाव।

नशाखोरी और सामाजिक विघटन- गांव . गांव में अवैध शराब विक्रय से हिंसक वारदात की घटना जिससे समाज एवं युवा बरबाद हो रहे है। ज्ञापन सौपने वालों में बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर मनीष आनंदए प्रदेश बसपा अध्यक्ष श्याम टण्डनए बसपा छग पूर्व विधायक इंदू बंजारेए के डी टण्डन आदि उपस्थित रहें।

कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें अधिकारी – कलेक्टर रणवीर शर्मा

मुख्यमंत्री कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस तैयारी एवं समय-सीमा बैठक में कलेक्टर ने दिए आवश्यक निर्देश

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला कार्यालय के दिशा भवन में बीते मंगलवार को कलेक्टर रणवीर सिंह शर्मा की अध्यक्षता में अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन स्तर पर संचालित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और जिले में पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशासन सुनिश्चित करने संबंधी निर्देश दिए गए। कलेक्टर शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी मांगी गई जानकारियां समय पर और स्पष्ट रूप में भेजें तथा मुख्यमंत्री एवं उच्च कार्यालय से प्राप्त निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। उन्होंने कर्तव्य निर्वहन में जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं दायित्वों का समयबद्धता से निर्वहन करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने यह भी कहा कि किसी भी कार्य में लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रतियोगिता परीक्षा में पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक-बैठक में जिले में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर परीक्षा की पारदर्शिता प्रभावित नहीं होनी चाहिए और किसी भी अवांछनीय गतिविधि की संभावना को प्रारंभिक स्तर पर ही निष्क्रिय किया जाए। परीक्षार्थियों को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप परीक्षा में सम्मिलित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री कार्यक्रम व स्वतंत्रता दिवस को लेकर विशेष निर्देश-कलेक्टर रणवीर शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रस्तावित जिले में संभावित आगमन को लेकर अधिकारियों को आवश्यक तैयारी रखने और विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन सुचारू और गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हो, यह सभी विभागीय अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी कड़ी में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व को गरिमामय और प्रेरणादायक ढंग से मनाया जाना चाहिए। इसके लिए सभी अधिकारी अपने-अपने विभागीय दायित्वों का पालन शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार करें और बेहतर तालमेल से कार्यक्रम को सफल बनाएं।

लंबित प्रकरणों के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश-बैठक के दौरान समय-सीमा के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों से कहा कि जनता से जुड़ी समस्याओं, आवेदनों व लंबित फाइलों का निराकरण गुणवत्तापूर्ण और निर्धारित समय-सीमा में किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनदेखी पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। कुल मिलाकर बैठक में प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में कलेक्टर रणवीर शर्मा ने स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे शासन की मंशा के अनुरूप जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में अपना श्रेष्ठ योगदान देंगे।

जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की बैठक संपन्न

कानून व्यवस्था और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सर्वोपरि - सख्त निगरानी और समन्वय से कार्रवाई के निर्देश

बेमेतरा/मूक पत्रिका

नशीली दवाओं की तस्करी और इसके बढ़ते दुष्प्रभावों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बीते मंगलवार को कलेक्टोरेट स्थित दिशा सभागार में कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एनकॉर्ड समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर एसएसपी रामकृष्ण साहू भी बैठक मे उपस्थित थे 7 बैठक का उद्देश्य जिले में ड्रग्स तस्करी की रोकथाम, इससे जुड़े अपराधों पर कठोर कार्रवाई और विभिन्न विभागों के बीच ठोस समन्वय स्थापित करना रहा। कलेक्टर शर्मा ने कहा कि नशीली दवाओं की अवैध गतिविधियां सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि समाज के ताने-बाने और विशेषकर युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा हैं। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को सतर्क रहते हुए आपसी समन्वय के साथ ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से पुलिस, खुफिया इकाइयों एवं प्रशासन को निर्देशित किया गया कि वे संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें, नियमित तलाशी अभियान चलाएं और जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई करें।बैठक में पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू ने स्पष्ट किया कि जिले के चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई जाएगी तथा तस्करों के विरुद्ध समय रहते कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि गुप्त सूचना तंत्र को सक्रिय कर ड्रग्स की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के प्रयास किए जाएं।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आमजन की भागीदारी से नशा विरोधी अभियान को व्यापक रूप दिया जाएगा। खासकर स्कूल, कॉलेज और ग्राम स्तर पर जनजागरूकता कार्यक्रम चलाकर युवाओं को नशे से दूर रहने हेतु प्रेरित किया जाएगा। इस मौके पर एडीएम डॉ. अनिल वाजपेयी, डीएसपी श्री राजेश झा, एनकॉर्ड समिति के सदस्यगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जन-जागरूकता अभियानों के साथ-साथ पुनर्वास और परामर्श सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में भी विचार-विमर्श किया गया।

'कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तीकरण' विषय पर हुआ आयोजन

कृषि महाविद्यालय ढोलिया में मनाया गया विश्व युवा कौशल दिवस

बेमेतरा/मूक पत्रिका

रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, ढोलिया में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तीकरण' विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के अधिष्ठाता ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि नया कौशल सीखना एक नई दुनिया को देखने जैसा है। हर युवा को इस अनुभव को महसूस करना चाहिए क्योंकि सीखना ही एक ऐसा गुण है जिसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि कृषि क्षेत्र में ढ्ढ का उपयोग पोषक तत्वों की पहचान, कीट व रोग नियंत्रण, मौसम पूर्वानुमान और सटीक कृषि (प्रिसिजन फॉर्मिंग) जैसे विभिन्न पहलुओं में किया जा सकता है। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त अधिकारी, कर्मचारीगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। युवा कौशल दिवस का यह आयोजन छात्रों में नवीन तकनीकों एवं डिजिटल दक्षताओं के प्रति जागरूकता लाने की दिशा में एक प्रभावी पहल सिद्ध हुआ।

पूर्व माध्यमिक शाला कोटेया में शाला प्रवेश उत्सव, न्योता भोज सह विदाई समारोह का भव्य आयोजन

सलका /मूक पत्रिका

अघिना पूर्व माध्यमिक शाला कोटेया में बीते सोमवार को शाला प्रवेश उत्सव सह विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया गया इस अवसर पर न्योता भोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानपाठक राजपाल सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर, सरस्वती वंदना के साथ किया गया। मंचासीन अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। छात्राओं ने स्वागत गीत एवं प्रेरणा गीत प्रस्तुत किया। अतिथियों ने शाला प्रवेश उत्सव के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। नवप्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर, पुस्तक प्रदान कर,मिष्ठान खिलाकर उनका स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया। सेवानिवृत्त प्रधान पाठक राजपाल सिंह ने अपने शिक्षकीय जीवन का अनुभव साक्षा करते हुए, मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन प्रदान किया। इस अवसर पर मनोज सिंह प्रधान पाठक प्राथमिक विद्यालय कोटेया ने कविता ,पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक बृजेन्द्र भारती ने विदाई गीत एवं शिक्षिका सृष्टि रानी ने अपने विचार अभिव्यक्त किया। प्रा शाला एवं पूर्व मा शाला के शिक्षक- शिक्षिकाओं ने राजपाल सिंह को शाल ,श्रीफल, डायरी, पेन, वस्त्र एवं विद्यालयीन गतिविधियों की फोटो फ्रेम भेंट कर सम्मानित किया। सेवा समिति सलका के सदस्य आशिष गुप्ता, फिरोज खान, राजेश गुप्ता, ज्ञानप्रकाश दुबे द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक को शाल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन पर सभी अतिथियों, शिक्षकों, पालकों एवं ग्रामीणों ने स्वादिष्ट न्योता भोज का आनंद लिया।कार्यक्रम के आयोजन में शिक्षक मनोज सिंह, बृजेन्द्र भारती, राधेश्याम सिंह, अंजू मार्को, सृष्टि रानी साण्डिल्य, पुष्पा सिंह का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन रीता गिरी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सलका संकुल प्राचार्य लालचंद सिंह पैंकरा, अघिना संकुल प्राचार्य चंद्रपाल कुशवाहा,सी एस सी सुनील चक्रधारी, पंकज गुप्ता, राजेश एक्का, प्रदीप पैंकरा,सूरज सिंह, राजेश अग्रवाल,कोटेया सरपंच कलेश्वर सिंह, सुशील कुशवाहा, मुनेश्वर राजवाड़े ,शिक्षिका कुसुम राजवाड़े,देवंती गुप्ता, संकुल के अन्य प्रा शाला एवं मा शाला के शिक्षक - शिक्षिका ,पालकों एवं ग्रामीणों की गरिमामय उपस्थिति रही।

छात्रवृत्ति भुगतान हेतु आधार सीडिंग व बैंक खाता अपडेट आवश्यक, 7 दिवस के भीतर करें त्रुटि सुधार

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2024-25 के अंतर्गत विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति भुगतान हेतु दिशा-निर्देश जारी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कॉलेज स्तर) योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान अब आधार सीडिंग किए गए बैंक खाते में सीधे किया जा रहा है। अतः ऐसे विद्यार्थी जिनका आधार सीडिंग इनएक्टिव है, या जिनका बैंक खाता गलत/बंद है, और जिनको वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, वे अपनी स्टूडेंट आईडी के माध्यम से पोर्टल में सही बैंक खाता की जानकारी दर्ज करते हुए त्रुटि सुधार अवश्य करें। विद्यार्थियों को यह कार्य अगले 07 दिवस के भीतर (जिनकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है) अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा। निर्धारित समयावधि में त्रुटि सुधार नहीं किए जाने की स्थिति में छात्रवृत्ति प्राप्त न होने की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी। यदि किसी विद्यार्थी को त्रुटि सुधार अथवा आधार सीडिंग प्रक्रिया में कोई समस्या आती है तो वे अपनी अध्ययनरत संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही, आदिवासी विकास विभाग, बेमेतरा के कलेक्टोरेट परिसर स्थित कक्ष क्रमांक-71 में छात्रवृत्ति शाखा से कार्यालयीन समय में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी चाहें तो छात्रवृत्ति पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।

विधायक अनुज के सवाल में फंसे उद्योग मंत्री, प्रश्न का दिया गोल-मोल जवाब

जायसवाल निको के लापरवाह उद्योग संचालन पर किया प्रश्न

रायपुर/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र 2025 के द्वितीय दिवस पर बीते मंगलवार को धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने अपने क्षेत्र में मनमाने ढंग से उद्योग संचालित करने वाली कंपनी जायसवाल निको पर उठाये महत्वपूर्ण सवाल7 विधायक अनुज शर्मा ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन को अपने प्रश्नों से घेरते हुए पूछा की क्या धरसींवा विधानसभा क्षेत्र स्थित मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लि. मि. सिलतरा के ब्लास्ट फर्नेस एवं पावर प्लांट में श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया व निरीक्षण में क्या-क्या विसंगतिया पाई गई? साथ ही निरीक्षण में जांच अधिकारी के द्वारा क्या किसी प्रकार का ÷प्रतिबंधात्मक आदेश ÷कारखाना प्रबंधन को जारी किया गया था? और इसे कब पुनः परीक्षण कर जांचा गया? इस सवाल का जवाब देने में मंत्री जी आना-कानी करते रहे तथा गोल-मोल जवाब देने लगे। मंत्री जी ने कहा की जाँच में कोई विसंगतिया नहीं पाई गई। जबकि पूर्व के सवालो से प्राप्त जवाब में बताया गया था की जायसवाल निको प्लांट की जाँच में लगभग 71 धराओ का उल्लंघन करना पाया गया है जिसमे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, संविदा श्रमिक अधि., वेतन भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, उपादान भुगतान अधिनियम, श्रम कल्याण निधि अधिनियम आदि के जाँच में अनियमितता के संबध प्लांट प्रबंधन द्वारा 03 दिनों के भीतर दिए गए जवाब से विभाग संतुष्ट होकर फाइल को नस्तीबद्ध कर दिया गया। ऐसे खानापूर्ति कार्यवाहियों से प्लांट प्रबंधनों की मनमानी बढ़ गई है। जायसवाल निको प्लांट का ऑक्सीजन प्लांट अति जर्जर एवं बेमरम्मति अवस्था में है, ऐसी घोर लापरवाहियां श्रमिकों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है जिसके लिए विधायक जी के माँग पर मंत्री द्वारा जाँच कराने का आश्वासन दिए है।

विधायक गुरु खुशवंत साहेब पर हमले के खिलाफ सतनाम सेना जांजगीर-चांपा ने जताया विरोध, SP को सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा की मांग

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

आरंग विधायक एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ शासन के उपाध्यक्ष गुरु खुशवंत साहेब पर बीते दिनों असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले की घटना के विरोध में अखिल भारतीय सतनाम सेना, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा ज़ोरदार विरोध दर्ज किया गया।जिला अध्यक्ष राजेश्वर बघेल के नेतृत्व में सतनाम सेना के पदाधिकारियों व समाजजनों का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँचा और एसपी विवेक पाण्डेय को ज्ञापन सौंपते हुए घटना के दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा गुरु खुशवंत साहेब को ˚+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की।

इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सतनाम सेना जिला अध्यक्ष राजेश्वर बघेल ने कहाः गुरु खुशवंत साहेब केवल विधायक नहीं, बल्कि हमारे गुरु भी हैं। उन पर हुआ हमला केवल एक जनप्रतिनिधि पर नहीं, बल्कि संपूर्ण सतनामी समाज की आस्था पर हमला है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।इस दौरान किरण कठौतिया (उपाध्यक्ष), शनि सूर्यवंशी (जिला मीडिया प्रभारी), जय कुमार लहरे, पंकज कुर्रे सहित अखिल भारतीय सतनाम सेना के कई पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे।गौरतलब है कि रायपुर और पाटन के बाद अब जांजगीर-चांपा में भी सतनामी समाज के लोगों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है।राज्यभर में सतनामी समाज द्वारा न्याय व सुरक्षा की मांग को लेकर ज्ञापन देने का सिलसिला तेज़ी से चल रहा है।

जनदर्शन में विभिन्न शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित 34 आवेदन प्राप्त हुए

कलेक्टर ने सुनी जनदर्शन में लोगों की समस्याएं

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर रणबीर शर्मा की उपस्थिति मे बीते मंगलवार को कलेक्टरेट के दृष्टि सभा कक्ष मे जनदर्शन आयोजित की गई। जिसमे जिले के अलग-अलग क्षेत्र के लोग अपनी-अपनी मांग, समस्याएं एवं शिकायतें लेकर आये। इस दौरान जनदर्शन मे आने वाले सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया गया। आज के जन चौपाल में कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को गौर से सुना और संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर और समक्ष बुलाकर संबंधित आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। कुछ आवेदन मौके पर ही निराकरण किए गए। आज जनदर्शन में विभिन्न शिकायत एवं समस्याओं से संबंधित 34 आवेदन प्राप्त हुए। तात्कालिक महत्व की समस्याओं का जहां त्वरित निराकरण किया। वहीं गंभीर और जांच के आवेदनों को टीएल पंजी पर दर्ज करके, इनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अफसरों को दी। इस दौरान जनदर्शन में दूरदराज के गांवों से अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पहुंचे लोगों में से तहसील साजा के ग्राम घोटवानी के निवासी तखतराम वर्मा ने शासकीय आने जाने के रास्ता को बंद किये जाने के संबंध में आवेदन दिया, तहसील साजा के ग्राम सोमई खुर्द के निवासी रोहित लाल साहू ने क्षति पूर्ति दिलाये जाने के संबंध में आवेदन दिया, तहसील नवागढ़ के ग्राम किरता के समस्त ग्रामवासी ने चिचोली से किरता सड़क को मरम्मत कराने के संबंध में आवेदन दिया, बेमतरा वार्ड नं. 11 गंजपारा निवासी रजनी साहू ने अपने पुत्र के ईलाज हेतु पैसा दिलाने के संबंध में आवेदन दिया, तहसील बेमेतरा के ग्राम करंजिया निवासी चित्रलेखा वैष्णव ने भूमि की नकल पटवारी द्वारा प्रदान करने के संबंध में आवेदन दिया। इसके अलावा आम नागरिकों ने निराश्रित पेंशन दिलाने, बैटरी चलित ट्रायसायकल हेतु, प्रधानमंत्री आवास दिलाने, कटा हुआ रकबा जोड़ने, खाद गड्ढा को हटाये जाने, आम रास्ता खुलवाने, वृद्धापेंशन हेतु, दिव्यांगता पेंशन दिलाये जाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए है। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए ग्रामीणों को आश्वासन दिलाया। इस अवसर पर सी.ई.ओ. जिला पंचायत टेकचंद अग्रवाल, अपर कलेक्टर डॉ. अनिल वाजपेयी, एसडीएम बेरला दिप्ती वर्मा सहित विभिन्न विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा स्वामी डीबी कार्प लिमिटेड के लिए प्लाट नम्बर 40/44 इंडस्ट्रियल एरिया बीरगांव रोड, उरला, रायपुर से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।